PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 263 ● भिलाई, बुधवार 29 अप्रैल 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

केंद्र सरकार सिक्किम में अवसंरचना सुविधाओं के विकास को दे रही है पूरी प्राथमिकता

गंगटोक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम में स्वच्छता और सौंदर्य तथा राज्य के लोगों की सौम्यता की प्रशंसा करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्य में अवसंरचना सुविधाओं के विकास को पूरी प्राथमिकता दे रही है।

मोदी राज्य के 50 स्थापना दिवस समारोह के समापन के अवसर पर पूर्वाह्न यहां आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, एक सबसे अच्छी बात मुझे पूरे रास्ते भर दिखाई वह थी, सिक्किम की सड़कों की स्वच्छता... दूर-दूर तक कोई गंदगी नहीं.. वायु में भी स्वच्छता, सड़कों पर भी स्वच्छता.. सिक्किम के आप लोग प्रकृति के पक्के संरक्षक हैं.. आप सिक्किम के सच्चे दूत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हम सिक्किम के संपर्क सुविधाओं और यहां अवसंरचना पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

बीते वर्षों में यहां सैकड़ों किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ है। गांव-गांव तक सड़कों को पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के लोगों को सस्ता इलाज सुलभ कराने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दे रही है। इसी संदर्भ में उन्होंने आयुष्मान योजना और इसके तहत के तहत 70 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए मुफ्ती इलाज की सुविधा तथा जेनेरिक दावों के लिए जन औषधि केंद्र योजना का उल्लेख किया। मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती का

सिक्किम का मॉडल देश के लिए प्रेरणा है और सिक्किम की जीवन शैली, सिक्किम के संकल्प देश के भविष्य के सपने का हिस्सा बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम में बहुत संभावना है। यहां की एक संभावना खेल को के क्षेत्र में है यहां के युवाओं ने खेलकूद के मैदान पर अपनी क्षमता और प्रतिभा को साबित किया है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार खेलो इंडिया और ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ देशभर में खेलकूद को प्रोत्साहित करने और सुविधाएं बढ़ाने का कार्यक्रम चल रही है। उन्होंने कहा कि सिक्किम ने अपनी विकास यात्रा में प्रगति की है सिक्किम और तेज गति से आगे बढ़े विकसित भारत के सपने को गति दे हमें इसके लिए मेहनत करनी है हमें सिक्किम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। मोदी ने कहा कि सिक्किम के पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था राज्य की एक बड़ी ताकत है। यह राज्य देश के कुल क्षेत्र का केवल एक प्रतिशत है पर यह भारत की वानस्पतिक विविधताओं के एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है राज्य में पक्षियों की 500 प्रजातियां पाई जाती है।

यहां 700 प्रकार की तितलियां, और कंचनजंगा की भव्य चोटिया दिखती है। राज्य प्राकृतिक सौंदर्य की छठ विकर्ता है सिक्किम दर्शकों को अभिभूत करता है और उन्हें यहां बार-बार आने के लिए आकर्षित करता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि सिक्किम और पूर्वोत्तर हमारे लिए केवल देश का एक हम हिस्सा ही नहीं है बल्कि यह भारत की अष्ट लक्ष्मी है। इसीलिए सरकार ने एक्ट ईस्ट की नीति पर काम शुरू किया है और पूर्वोत्तर में (एक्ट फास्ट) और अधिक तेजी से काम करने का संकल्प भी लिया है।

बंगाल चुनावः दूसरे चरण का मतदान, भाजपा एवं तृणमूल दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी

कोलकाता। पहले चरण में 93 प्रतिशत से अधिक के रिकॉर्ड मतदान और तृणमूल कांग्रेस तथा भाजपा के दावों के साथ, पश्चिम बंगाल चुनाव अब अपने सबसे निर्णायक चरण में पहुँच गया है, जहाँ बुधवार को आठ जिलों के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। कोलकाता और दक्षिण बंगाल पारंपरिक रूप से तृणमूल का मजबूत गढ़ माने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छह जनसभाएं और दो रोड शो करने के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा इस रुझान को तोड़ने के लिए बेताब है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस चरण में एक करोड़, 64 लाख ,35 हजार, 627 पुरुष, एक करोड़, 57 लाख, 37 हजार, 418 महिलाएं और 792 तीसरे लिंग के मतदाताओं सहित कुल तीन करोड़, 21 लाख, 73 हजार, 837 मतदाता 41,001 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी की व्यवस्था होगी। इन जिलों की सामाजिक संरचना, मतदाताओं की संख्या और विविधता इस चरण को न केवल संख्यात्मक बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती है। निर्वाचन क्षेत्र आठ प्रमुख जिलों- उत्तर कोलकाता (7 सीटें), दक्षिण कोलकाता (4), उत्तर 24 परगना (33), दक्षिण 24 परगना (31), हावड़ा (16), नदिया (17), हुगली (18) और पूर्व बर्धमान (16) में फैले हुए है, जिनमें तीन जिलों में अंतरराष्ट्रीय और नदी सीमाएं इसे न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। जनसांख्यिकीय रूप से, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और दक्षिण कोलकाता के बड़े हिस्सों में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी है।

श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस, 'ई-श्रम साथी' एप लॉन्च

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के कार्यों और योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैदानी अमला पूरी प्रतिबद्धता के साथ श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखन देवांगन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में श्रमिकों के हित में व्यापक पहल हुई है और चार नई श्रम संहिताएं लागू की गई हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि श्रमिकों को सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रम विभाग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जो बड़े पैमाने पर श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण भी तकनीक के माध्यम से किया जाए, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक 29 अप्रैल को अपरान्ह साढ़े तीन बजे से मंत्रालय (महानदी भवन), नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की जाएगी। इस आशय का पत्र आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री एवं जनजातीय सलाहकार के परिषद के उपाध्यक्ष रामविचार नेताम सहित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।

राज्य सरकार के इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-श्रम साथी मोबाईल एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ डिजिटल लेबर चौक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मेहनत देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है, इसलिए उनके योगदान का सम्मान और उनके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। समीक्षा बैठक में श्रम विभाग की संरचना, श्रमायुक्त संगठन, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा तीनों प्रमुख मंडलों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रदेश के सभी जिलों में श्रम कार्यालयों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ दोनों सुनिश्चित हो सके।

वैश्विक शांति के लिए खतरा

भारत ने होर्मुज से सुरक्षित समुद्री मार्ग बहाल करने का किया आग्रह, जहाजों पर हमलों की निंदा की

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित एवं निर्बाध समुद्री आवागमन को तत्काल बहाल करने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में वाणिज्यिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमले वैश्विक शांति, ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के एजेंडे के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र में जलमार्गों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस में

भारतीय प्रतिनिधि योजना पटेल ने इस बात पर बल दिया कि महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा वैश्विक व्यापार एवं स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। जलमार्गों की सुरक्षा के लिए नए सिरे से अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करते हुए, पटेल ने कहा कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं और इनके परिणामस्वरूप पहले ही भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है जो बढ़ती समुद्री असुरक्षा की मानवीय कीमत को दर्शाती हैं। उन्होंने जोर दिया कि होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा वहन करते हैं और किसी भी व्यवधान के अंतरराष्ट्रीय स्थिरता के लिए दूरगामी परिणाम होते हैं। पटेल ने कहा कि महत्वपूर्ण जलमार्गों के लिए किसी भी खतरे का अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का अधिकांश प्रवाह इन्हीं मार्गों से होता है।

जनरल द्विवेदी ने सैनिक स्कूल रीवा में पूर्व कैडेट के तौर पर पुरानी यादें ताजा की

नयी दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिक स्कूल रीवा का दौरा किया जहां उन्होंने पूर्व कैडेट के तौर पर पुरानी यादों को ताजा किया। जनरल द्विवेदी इस स्कूल में केवल थल सेना प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्व कैडेट के रूप में लौटे थे, जिन्हें इस संस्थान के अनुशासन और आदर्शों ने आकार दिया था। सेना प्रमुख की यात्रा के दौरान वे गलियारे, जो कभी उनकी प्रारंभिक आकांक्षाओं की गूंज से भरे रहते थे, अब उनकी पूर्ण हुई यात्रा के साक्षी बने, जहां गर्व और स्मृतियाँ एक साथ मिलकर हर युवा कैडेट को प्रेरित कर रही थीं। उनका यह दौरा

मात्र औपचारिक नहीं था, बल्कि यह एक सशक्त स्मरण था कि इन कक्षाओं और परेड मैदानों में बोए गए। नेतृत्व के बीज एक दिन राष्ट्र का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह यात्रा संस्थान और उसके एक विशिष्ट पूर्व छात्र के बीच स्थायी संबंध को दर्शाती है, जिनकी अनुशासन, साहस और नेतृत्व की यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। सेना प्रमुख ने विद्यालय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्पांजलि अर्पित की, कैडेटों द्वारा प्रभावशाली गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।

वैश्विक सहयोग मजबूत करने और संयुक राष्ट्र चार्टर के प्रति नयी प्रतिबद्धता की जरूरत : बेयरबॉक

नयी दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80 वें सत्र की अध्यक्ष एनेलेना बेयरबॉक ने बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव के बीच वैश्विक सहयोग को मजबूत करने तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता की अपील की है। बेयरबॉक ने विदेश मंत्री डा एस जयशंकर के साथ मंगलवार को यहां वार्ता के बाद एक प्रेस वार्ता में कहा कि बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र, बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून केवल दबाव में नहीं हैं, बल्कि सीधे हमले के अधीन हैं। उन्होंने शांति एवं सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार के स्तंभों में बढ़ते विखंडन और तनाव की ओर भी संकेत किया। बेयरबॉक ने जोर देकर कहा कि कोई भी देश अकेले आपस में जुड़ी वैश्विक चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 जैसे वैश्विक स्वास्थ्य संकट, तथा यूक्रेन युद्ध सहित संघर्षों और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के आर्थिक प्रभावों पर भी विचार रखे। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना सभी के हित में है।

सरकार की योजनाओं को संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा : भाजपा

जयपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जयपुर में पदाधिकारियों एवं कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक ली जिसमें संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को संगठन के माध्यम से आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का निर्णय लिया गया हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बैठक के बाद

सोमवार रात मीडिया को बताया कि बैठक में इसके साथ ही संगठन को अधिक सक्रिय, मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए नियमित बैठकों एवं प्रवास कार्यक्रमों को गति देने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में संगठन विस्तार, केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। डॉ चतुर्वेदी ने बताया कि मंडल, जिला एवं प्रदेश स्तर पर नियमित बैठकों के आयोजन, कार्यप्रणाली की समीक्षा तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योजनाओं को धरातल पर लागू करने की रूपरेखा भी तैयार की गई। इसके अलावा मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रमों के दौरान योजनाओं की समीक्षा एवं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। कोर कमेटी की बैठक में नारी शक्ति वंदन अभियान पर भी विशेष चर्चा की गई।

तमिलनाडु चुनावः मतों की गिनती चार मई को 62 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी

चेन्नई। तमिलनाडु की मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक ने मंगलवार को कहा कि गत 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती चार मई को राज्य भर के 62 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। यहां जारी एक विज्ञप्ति में सुश्री पटनायक ने कहा कि मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलट) की गिनती शुरू की जाएगी। इसके 30 मिनट बाद यानी सुबह 8.30 बजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में दर्ज मतों की गिनती शुरू होगी। ईवीएम वोटों की गिनती के दौर में अंतिम दौर की शुरुआत तभी होगी जब सभी डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाएगी। प्रत्येक मतगणना केंद्र में एक अनुभाग डाक मतपत्रों के लिए और दूसरा ईवीएम वोटों के लिए समर्पित होगा, जहाँ निर्धारित मेजों पर मतगणना की जाएगी। डाक मतपत्रों की गिनती प्रत्येक 500 डाक मतपत्रों के लिए एक मेज के अनुपात में की जाएगी। प्रत्येक अनुभाग की निगरानी के लिए अलग सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ स्तर) नियुक्त किए जाएंगे।

पुलिस कर्मियों, जोनल/सेक्टर अधिकारियों और निगरानी टीम के सदस्यों सहित कुल 3.36 लाख चुनाव अधिकारियों ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया, जबकि 1.10 लाख अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र (ईडीसी) का उपयोग करके सीधे मतदान केंद्रों पर मतदान किया।

शेयर बाजारों में शुरुआती गिरावट

मुंबई। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों और रुपये पर जारी दबाव के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में प्रमुख सूचकांक गिरावट में खुले, लेकिन बाद में हरे निशान में पहुंच गये। बीएसई का सेंसेक्स 208.84 अंक टूटकर 77,094.79 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह

32.26 अंक (0.04 प्रतिशत) फिसलकर 77,271.37 अंक पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 42.80 अंक नीचे 24,049.90 अंक पर खुला, लेकिन बाद में हरे निशान में पहुंच गया। खबर लिखे जाते समय यह 14.30 अंक यानी 0.06 प्रतिशत ऊपर 24,107 अंक पर था। दूसरे एशियाई बाजारों और रुपये में रही गिरावट से घरेलू शेयर बाजारों में निवेश धारणा प्रभावित हुई है।

19 हजार श्रद्धालु इन सेवाओं का लाभ ले चुके

पांच दिनों के भीतर डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन

देहरादून/रूद्रप्रयाग। उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग जनपद अंतर्गत स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा इस वर्ष सफलता की नई मिसाल पेश कर रही है। यात्रा शुरू होने के मात्र पांच दिनों के भीतर ही डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं।

बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल, हेलीकॉप्टर, डंडी-कंडी के साथ-साथ घोड़े-खच्चरों के माध्यम से धाम तक पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रा सुगम और व्यवस्थित बनी हुई है। यह यात्रा घोड़ा-खच्चर के संचालन से काफी सुगम हुई है। इन घोड़ा खच्चरों के लिए 19 स्थानों पर गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशीष रावत ने बताया कि इस वर्ष 8,300 घोड़े-खच्चरों का फिटनेस परीक्षण किया गया है, जबकि 7,359 का डिजिटलीकरण कर पंजीकरण सुनिश्चित किया गया है। इन्हीं पंजीकृत पशुओं का उपयोग श्रद्धालुओं के आवागमन और माल ढुलाई में किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 19 हजार श्रद्धालु इन सेवाओं का लाभ ले चुके हैं। पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छह स्थानों पर अनवरत गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, वहीं 13 स्थानों पर गीजर के माध्यम से गर्म पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। बिना लाइसेंस और बीमा के संचालन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब तक तीन एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।

डॉ रावत ने बताया कि इसके अलावा सोनप्रयाग, गौरीकुंड, बड़ी लिनचोली और रुद्रा प्वाइंट में पशु चिकित्सालय संचालित किए जा रहे हैं, जबकि भीमबली में चेकिंग प्वाइंट स्थापित किया गया है। गौरीकुंड में घोड़े-खच्चरों का गहन परीक्षण और दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की एसओपी के तहत संचालित यह व्यवस्थाएं न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित कर रही हैं, बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम में बच्चों के संग खेला फुटबॉल

गंगटोक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन मंगलवार सुबह यहां एक मैदान में बच्चों के साथ कुछ समय फुटबॉल खेला। मोदी ने मैदान पर अपने हाथ में फुटबॉल लेकर बच्चों के साथ अपनी तस्वीर साझा कीं। फुटबॉल की पोशक पहने बच्चों की टोली में किशोर वय बालक और बालिकाएं शामिल थे। प्रधानमंत्री एक चित्र में गोल पोस्ट के सामने से गोल कर रहे हैं और गोल्ड कीपर उसे पकड़ने में सफल हो गया है। अन्य युवा खिलाड़ी ताली बजाकर प्रधानमंत्री के प्रदर्शन का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों के साथ लिखा, साफ दिखता है, इन किशोर

खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेलना ऊर्जा भरने वाला रहा। मोदी सिक्किम राज्य के 50 वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सोमवार शाम यहां पहुंचे थे और एक रोड शो में भाग लिया था। मोदी ने कल शाम को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित और अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले राज्य के कुछ लोगों से मुलाकात की।

जनपद कर्मचारियों के लिए बना आवास में एम्बुलेंश चालक पशु अधिकारी सहित अन्य का कब्जा

गरियाबंद। देवभोग जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया शासकीय आवास पर विभाग के कर्मचारियों को नसीब नहीं हो रहा है तो दूसरी ओर एम्बुलेंश चालक ओम कुमार साहू पशु अधिकारी भीष्म कुमार साहू जैसे अन्य विभाग के अधिकारी उक्त विभाग का उपयोग कर रहे है और यह स्तिथि न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि वास्तविक पात्र कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं माना जा रहा है क्योंकि ऐसे अधिकारी कर्मचारी अपने विभाग के अलावा हाऊसिंग बोर्ड में आवास है बावजूद इसके जनपद परिसर के आवास में निवासरत है उल्लेखनीय हो कि जनपद पंचायत कार्यालय के समीप करीब 6 आवास बनाया गया है जहां वर्षों पहले जनपद स्टाफ निवास करता था लेकिन अब उक्त आवासो में जनपद पंचायत से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बजाय अन्य विभागों के कर्मचारी निवास कर रहे हैं जो कि निर्धारित नियमों के विपरीत है सूत्रों का कहना है कि जनपद परिसर के आवास केवल संबंधित विभाग के कर्मचारियों के लिए ही आवंटित किए जाने चाहिए लेकिन वर्तमान में कई आवासों पर बाहरी विभागों के कर्मचारियों ने कब्जा जमा रखा है इससे न केवल पात्र कर्मचारियों को आवास नहीं मिल पा रहा है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है स्थानीय लोगों एवं कर्मचारियों

ने इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है उनका कहना है कि यदि जल्द ही इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है क्योंकि जनपद कार्यालय में ऐसे कई कर्मचारी अधिकारी पदस्थ है जो 12 से 15 किलोमीटर दूर अपने गांव घर जाकर निवास करते है और रोजाना आवागमन कर अपने पंचायती काम काज करने को मजबूर हैं इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है अब देखना होगा कि प्रशासन इस अनियमितता पर कब तक सख्त कदम उठाता है ।

कर्मचारियों को मिलती राहत

सबसे दुख की बात तो यह कि जनपद पंचायत में ऑपरेटर बाबू है जो देर रात तक जनपद कार्यालय में काम करते हैं और उन्ही कर्मचारियों 12 किलोमीटर दूर देर रात अपने गांव कदलीमुड़ा या बरकानी दहीगांव सहित अन्य जाना पड़ता हैं जिससे स्थानीय सीईओ सहित तमाम अधिकारी अवगत है लेकिन अफसोस कि बात है जनपद पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों को राहत दिलाने के लिए कोई पहल अब तक नही हो पाया हैं जबकि बरसात के दिनों ऐसे कर्मचारियों घर से आने जाने काफ़ी ज्यादा परेशान होना पड़ता है फिर भी जिम्मेदार अधिकारी अधिकारियों को परेशानी नजर नही आ पाता इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया जाता हैं हलाकि इसके कुछ जनप्रतिनिधि उच्च अधिकारियों को अवगत करते आवासो खाली कराने की मांग करने की बात कह रहे हैं ताकि जनपद कार्यालय के कर्मचारियों को आवास आंबटित किया जाए।

तालपत्री के सहारे बरसात के पानी को रोकने की कोशिश

जनपद कर्मचारी के नहीं होने और जनपद अधिकारियों के उदासीनता रवैया के चलते आवास खंडहर की स्थिति में दिखाई पड रहा हैं बरसात के पानी से बचने के लिए तालपत्री का सहारा लिया जाता हैं इसका कारण संबंधित विभाग द्वारा ऐसे आवासों का समय समय पर रख रखाव नहीं करने को माना जाता हैं और यही स्थिति रहा तो आगामी दिनों यह शासकीय आवास पूरी तरह निस्त नाबूत होने की पूरी संभावना बन रही यही वजह की जिला सीईओ से आवास की मरम्मत कर जनपद कर्मचारियों को आवास आंबटित करने की मांग करेंगे ताकि देर रात कार्य करने वाले कर्मचारियों को सहूलियत मिल सके।

जिले के 53 ग्रामों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि मैनपुर विकासखण्ड के गरीबा, कोदोमाली, गौरगांव व आसपास के ग्राम इस प्रकार वर्तमान में मैनपुर विकासखंड के अंतर्गत 45 ग्राम तथा गरियाबंद विकासखंड के अंतर्गत 08 ग्राम, इस प्रकार कुल 53 ग्राम गैर-परंपरागत तरीके सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत हैं। उन्होंने बताया कि इन ग्रामों में स्थापित सौर संयंत्र का संचारण-संधारण क्रेडा विभाग के माध्यम से किया जाता है। परंपरागत तरीके से (ग्रिड) के माध्यम से विद्युतीकरण करने के लिए लगातार उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित की गई है। उन्होंने बताया कि यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियम प्रकाशन तिथि 08 जून 2023 के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व में विद्युतीकरण यथा-33 केव्ही एवं इससे निम्न वोल्टेज की विद्युत लाईनों हेतु भूमिगत केबल के माध्यम से किये जाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। जिले के कुल 53 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु प्रावधान 294.00 किलोमीटर 11 केव्ही लाईन, 117.61 किमी. एल.टी. लाईन तथा 187 नग ट्रांसफार्मर इसकी कुल राशि 900 करोड़ 63 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। उक्त अनुमानित राशि के लिए वर्तमान में लागू राशि भी शामिल है तथा विद्युत कंपनी द्वारा वर्तमान में लागू सेड्यूल ऑफ रेट 2025-26 अनुसार प्राक्कलन राशि की गणना की गई है। इन ग्रामों को परंपरागत तरीके से विद्युतीकरण हेतु अत्यधिक बजट/फंड की आवश्यकता होगी। अतः प्रशासकीय स्वीकृति एवं वन विभाग से अनुमति उपरांत उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य किया जाना संभव होगा। ओड़िशा राज्य से देवभोग क्षेत्र के अंतिम छोर में स्थित कोदोमाली, ग्राम पंचायत साहेबिनकछार में 11 के.व्ही. विद्युत लाईन की अनुमति के बारे में बताया गया है कि ग्राम कोदोमाली के परंपरागत तरीके से विद्युतीकरण हेतु प्रकरण ओड़िसा राज्य के विद्युत नियामक आयोग में अनुमति हेतु प्रक्रियाधीन है।

नए पुलिस अधीक्षक के सामने अवैध गतिविधियों पर अंकुश की बड़ी चुनौती

बलौदाबाजार। जिले में नए पुलिस अधीक्षक के रूप में ओमप्रकाश शर्मा की नियुक्ति के साथ ही जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और बढ़ती आपराधिक एवं अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की चुनौती सामने आ गई है। 10 जून 2024 की एक चर्चित घटना के बाद से संवेदनशील माने जाने वाले इस जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर आमजन की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश शर्मा इससे पहले भी बलौदाबाजार एवं भाटापारा क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिससे स्थानीय परिस्थितियों और चुनौतियों की उन्हें अच्छी समझ है। ऐसे में जिलेवासियों को उनसे ठोस और प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद है। जिले में बीते कुछ समय से अपराधों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। खासकर चोरी की घटनाएं आमजन के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में सेंधमारी, दुकानों में चोरी, वाहनों से बैटरी और डीजल की चोरी जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि कई मामलों में छोटी-छोटी चोरी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। पूर्व पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल में किसानों के खेतों से सोलर पैनल और पंप की चोरी जैसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई थी, लेकिन बाद में अपराध के आंकड़े कम दिखाने के उद्देश्य से छोटी चोरी के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में कोताही बरतने की शिकायतें भी सामने आई। इसका सीधा लाभ असामाजिक तत्वों को मिलता रहा। जिले में कुछ स्थानों पर घुमंतू गिरोहों की सक्रियता भी देखी गई है, जो सुनसान इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न संगठनों द्वारा भी पूर्व में पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ सके।

सूचना तंत्र मजबूत कर पुलिस महकमे को सक्रिय करना समय की आवश्यकता

ऑफलाइन-ऑनलाइन सट्टा का फैलता जाल

जिले में सट्टा कारोबार भी अब संगठित रूप ले चुका है, जो कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। पहले जहां सट्टा पर्चियों के माध्यम से संचालित होता था, वहीं अब इसका स्वरूप तेजी से बदलकर डिजिटल हो गया है। सूत्रों के अनुसार, जिला मुख्यालय में ऑफलाइन सट्टा संचालन का कार्य बाय पास रोड स्थित ढाबा संचालक के द्वारा किया जा रहा है, जो पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा है। वर्तमान में सट्टा लिखने के लिए पारंपरिक पर्चियों के बजाय मोबाइल नंबरों और कॉल के माध्यम से दांव लगाए जा रहे हैं। इससे सट्टा कारोबार का दायरा बढ़ा है और इसे पकड़ना पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर मोबाइल एप और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए ऑनलाइन सट्टा भी संचालित किया जा रहा है। इस हाईटेक तरीके से चल रहे अवैध कारोबार पर निगरानी रखना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। हालांकि पुलिस को इस संबंध में समय-समय पर सूचनाएं मिलती रही हैं, लेकिन व्यापक और ठोस कार्रवाई के अभाव में सट्टा संचालन पर स्थायी रोक नहीं लग पा रही है। कई मामलों में छोटी कार्रवाई के बाद यह कारोबार फिर से शुरू हो जाता है, जिससे इसकी जड़ें और मजबूत होती जा रही हैं।

मीडिया की स्वतंत्रता और सुरक्षा भी अहम मुद्दा

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी वर्तमान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है। अपेक्षा की जा रही है कि जिले में मीडियाकर्मी निर्भीक और निडर होकर समाचारों का संकलन एवं प्रकाशन कर सकें तथा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी दबाव या भय के कर सकें। सूत्रों के अनुसार, जिला मुख्यालय में कुछ व्यक्ति यों का प्रभाव ऐसा बताया जाता है, जिन पर पूर्व में भयादोहन, ठगी और अन्य आपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता के आरोप लगे हैं और वर्तमान में वे जमानत पर हैं। ऐसे तत्वों के कारण अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, पुलिसकर्मियों एवं पत्रकारों पर अनावश्यक दबाव या भय का वातावरण बनने की चर्चाएं सामने आती रही हैं। ऐसी स्थिति में नए पुलिस अधीक्षक के समक्ष यह भी एक चुनौती है कि वे कानून के दायरे में रहकर ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें, ताकि सभी वर्ग निर्भय होकर अपने-अपने कार्य कर सकें और जिले में स्वस्थ एवं पारदर्शी वातावरण कायम हो सके।

अन्य अवैध गतिविधियों पर भी सख्ती जरूरी

सट्टा के अलावा जिले में अवैध शराब, सूदखोरी ब्याजखोरी और कुछ होटलों में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें भी मिलती रही हैं। ऐसे मामलों में भी प्रभावी और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए केवल पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक और मजबूत सूचना तंत्र का सहारा लेना होगा। स्थानीय स्तर पर मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर तथा तकनीकी निगरानी बढ़ाकर ही अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। नए पुलिस अधीक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती आमजन का भरोसा जीतने की है। यदि पुलिस समयबद्ध कार्रवाई, पारदर्शिता और सख्ती के साथ कार्य करती है, तो निश्चित रूप से जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार संभव है।

अध्यक्ष ज्योति भानु चन्द्राकर की अध्यक्षता में हुई पीआईसी की बैठक

कुरूद । नगर पालिका कुरूद अध्यक्ष कक्ष में नगरपालिका का आठवां पी.आई.सी. बैठक अध्यक्ष ज्योति भानु चन्द्राकर के अध्यक्षता मे आहुत किया गया, बैठक में मा. अध्यक्ष ज्योति भानु चन्द्राकर के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लोकसभा में विपक्ष द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं करने पर कांग्रेस सहित विपक्षीय दलों के लिए निंदा प्रस्ताव पास किया गया, इस विषय मे कुरूद नगरपालिका अध्यक्ष महिला होने के अपने दर्द को बयां करते हुए बताया केन्द मे विपक्षीय दलों द्वारा महिला विधेयक बिल को पास नही करना महिलाओं के अधिकारों के विरोध में विपक्षीय दलों के लिये नगरपालिका अध्यक्ष और 4 विभागों के पार्षद सभापति सदस्यों द्वारा निंदा प्रस्ताव पास किया गया, नगरपालिका उपाध्यक्ष एवं शिक्षा समिति के सभापति देवव्रत साहु ने इसका विरोध करते हुए भाजपा शासन जबरदस्ती विपक्षी दलों के लिए भ्रामक प्रचार कर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है जो कि उचित नहीं है और हम विषय का विरोध करते है ! नगरपालिका अध्यक्ष ने विपक्षी दलों के लिए निंदा प्रस्ताव सहित नगर विकास के 10 बिंदुओं वाली एजेण्डा में मुख्यरूप से नगर के प्रत्येक वार्डो में 15 वें वित्त से सभी वार्डो मे विभिन्न रोड, नाली, पानी, बिजली, स्वच्छता सहित मूलभूत कार्य के लिए लगभग 1.5 करोड़ से अधिक राशि की प्रस्ताव शासन को भेजने सर्व सम्मति से निर्णय किया गया, साथ ही अध्यक्ष महोदया के घोषणानुसार केनाल रोड कुरूद में चन्द्राकर भवन के सामने छत्रपति शिवाजी चौक सौन्दर्यीकरण, तहसील कार्यालय के बाजू मे सुभाष चन्द्र बोस चौक सौंदर्यीकरण, कारगिल चौक सौंदर्यीकरण कार्य, बायपास रोड में घड़ी चौक सौंदर्यीकरण, नया बस स्टैंड में महारानी अहिल्याबाई होल्कर सौंदर्यीकरण कार्य के लिए सर्व सम्मति से निर्णय किया गया, उसी प्रकार ग्रीष्मकालीन जल संकट से निपटने पेयजल हेतु बोरखनन कार्य, छोटा पानी टंकी निर्माण कार्य, कचरा डम्पिंग हेतु आकर्षक कचरादान, आवश्यक पेयजल कार्य, सहित नगर के समस्त प्रमुख मार्गो, मुक्तिधाम मार्ग, सार्वजनिक जगहों मे, तालाबों के चारों तरफ़ जिसमें बस्ती लगा हो, सभी मेनरोड में पर्याप्त मात्रा में बिजली आक्टेंगल पोल सड़कों मे आकर्षक विद्युत लाइट के लिए लगाने शासन को प्रस्ताव भेजने निर्णय लिया गया, अगामी बरसात से निपटने के लिए 3 माह के लिए नगर के सभी नालियों को सफ़ाई करने अतिरिक्त स्वीपर रखने के लिए भी निर्णय किया गया ! नगर को सुंदर बनाने एवं व्यवस्थित कुरूद बनाने संबंधी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए स्वीकृति अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष सहित सभी सभापतिगण बैठक में सम्मिलित होकर नगर विकास के लिए सर्व सम्मति से निर्णय किये. बैठक में नगर पालिका कुरूद के अध्यक्ष ज्योति भानु चन्द्राकर , सभापतियों में उपाध्यक्ष देवव्रत साहु , मिथलेश बैस , महेन्द्र गायकवाड़ , सितेश सिन्हा , राजकुमारी ध्रुव , विधायक प्रतिनिधि भानु चन्द्राकर , सलाहकार समिति के सदस्यगण रवि मानिकपुरी , मुख्य नगर पालिका अधिकारी गुप्ता, इंजीनियर पैंकरा एवं कर्मचारीगण सम्मिलित हुए। अध्यक्ष ज्योति भानु चन्द्राकर ने कुरूद नगरवासियों को बधाई देते हुए कहा कुरूद नगर में विष्णु के सुशासन और अजय के विकास रथ को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हम सब तेज गति से काम करते रहेंगे।

चिटफंड कंपनी पल्स इंडिया कंपनी लिमिटेड के फरार 02 आरोपी डायरेक्टर गिरफ्तार

बलौदाबाजार। चिटफंड कंपनी पल्स इंडिया कंपनी लिमिटेड (पीएसीएल कंपनी इंडिया लिमिटेड) के डायरेक्टर एवं एजेंटो द्वारा विभिन्न समयावधि में पैसे जमा करने पर अधिक ब्याज प्रदान करने का लालच देते हुए लोगों से पैसा जमा करवाया गया, जिसमें निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के बाद भी निवेशकों का पैसा कंपनी द्वारा वापस नहीं किया गया। कि प्रकरण में प्रार्थी पंचराम साहू रिपोर्ट पर दिनांक 07.11.2016 को थाना पलारी में अपराध क्रमांक 471/2016 धारा 420,34 भादवि, 10 छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 4,5,द प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए प्रकरण में संलिप्त एवं चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर आदि सहित कुल 09 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, किंतु प्रकरण में शामिल अन्य आरोपी अभी भी फरार थे। कि प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता द्वारा अधिक पैसे देने का प्रलोभन देकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले पीएसीएल चिटफंड कंपनी के फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु थाना प्रभारी पलारी को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के परिपालन में थाना पलारी पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए फरार आरोपियों के संबंध में लगातार पता तलाश किया जा रहा था। इसी बीच पता चला कि प्रकरण में फरार दो आरोपी EOW सेक्टर कानपुर जिला जालौन के एक प्रकरण में जिला जेल उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश में निरूद्ध है। कि सूचना पर थाना पलारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत आरोपी गुरजंत सिंह एवं गुरनाम सिंह को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा पीएसीएल कंपनी के माध्यम से लोगों को अधिक पैसे देने का लालच देते हुए उनसे ठगी करना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में दोनों आरोपियों को आज दिनांक 24.04.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। पीएसीएल चिटफंड कंपनी के विरुद्ध 128 निवेशकों से कुल 38,18,310 रकम ठगी का मामला पंजीबध्द किया गया है। प्रकरण में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम- 1. गुरनाम सिंह उम्र 59 वर्ष निवासी 5 जसरान थाना चम्कौर साहिब जिला रोपड़ पंजाब, गुरुजंत सिंह उम्र 80 साल निवासी मकान नंबर 2117 मोहाली 160062 एकलव्य अपार्टमेंट सेक्टर जिला मोहाली पंजाब।

मकान तोड़ने की कार्रवाई पर न्यायालय की रोक, प्रशासन को फटकार

प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नष्ट होने पर भी उठे सवाल

बलौदाबाजार। ग्राम कुकदा निवासी जगदीश मिरी के मकान तोड़े जाने की कार्रवाई पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने प्रशासन की कार्यवाही को प्रथम दृष्टया अवैध मानते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं तथा वाद भूमि पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूमिहीन होने के कारण जगदीश मिरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र मानते हुए जनपद पंचायत द्वारा सर्वे एवं अनुशंसा के बाद शासन ने उन्हें अन्य 107 हितग्राहियों के साथ आबादी भूमि पर मकान आवंटित किया था। यह मकान उन्हें वैध अधिकार के तहत प्रदान किया गया था।

बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों शिवप्रसाद, दुकालू, राधेश्याम, देवदास, विश्वनाथ, मोहनलाल, कृष्णकुमार, सियाराम और सुंदरलाल को यह आवंटन आपत्तिजनक लगा। आरोप है कि 23 जुलाई 2025 की रात इन लोगों ने एकजुट होकर जगदीश मिरी के घर पर हमला किया, दरवाजा व दीवार तोड़ दी, गाली-गलौज की और नगदी, जेवर व अनाज भी लूट ले गए।

पीड़ित द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी, भाटापारा द्वारा संबंधित ग्रामीणों के प्रभाव में आकर उक्त मकान को अवैध कब्जा घोषित करते हुए तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। तहसीलदार द्वारा बेदखली वारंट भी जारी किया गया, जबकि कलेक्टर स्तर पर भी प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। यह भी उल्लेखनीय है कि उसी आबादी भूमि पर बने अन्य व्यक्तियों के मकानों को नहीं तोड़ा गया। केवल जगदीश मिरी के मकान पर की गई इस कार्रवाई को लेकर भेदभाव के आरोप भी सामने आ रहे हैं। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त शासकीय सहायता राशि भी मकान तोड़े जाने के कारण नष्ट हो गई, जिससे सरकारी धन की हानि होना बताया जा रहा है। न्याय के लिए अंततः जगदीश मिरी ने अपने अधिवक्ता सतीश चन्द्र श्रीवास्तव के माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत नोटिस प्रेषित कर न्यायालय में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई करते हुए व्यवहार न्यायाधीश कु. रिद्धि बुराड ने प्रशासन की कार्रवाई को अवैध मानते हुए स्थगन आदेश पारित किया। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वाद भूमि पर जगदीश मिरी के कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। साथ ही संबंधित ग्रामीणों एवं प्रशासनिक अधिकारियों अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को भी हस्तक्षेप से रोका गया है। मामले में जगदीश मिरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चन्द्र श्रीवास्तव ने पैरवी की।

लोक अदालतों के माध्यम से समाधान हो जाने पर पक्षकारों व आम जनता में बढ़ा विश्वास

सरायपाली। नेशनल लोक अदालत को मिल रही सफलता के पीछे पक्षकारों के आपसी समझौता, समझ व सहयोगात्मक दृष्टिकोण की वजह से लोक अदालतों को निरंतर सफलता मिल रही है। वर्षों से न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों को मिनटों में लोक अदालतों के माध्यम से समाधान हो जाने से पक्षकारों व आमजनता में लोक अदालतों के आयोजनों के प्रति सम्मान व विश्वास दोनों बढ़ा है। इस सफलता में पक्षकारों , अधिवक्ताओं, पीड़ितों व मीडिया का अहम योगदान है जिनकी वजह से लगातार लोक अदालतों के आयोजनों को सफलता मिल रही है। उक्त कथन सरायपाली न्यायालय में पदस्थ अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार के दौरान व्यक्त किया गया । आगामी 9 मई को न्यायालय भवन में आयोजित लोक अदालत शिविर के संबंध में जानकारी देते हुवे एडीजे

वंदना देवांगन ने कहा कि आप सभी के इन प्रयासों व सहयोगात्मक दृष्टिकोण के कारण ही पक्षकारों के न्यायालयों में वर्षों से न्याय के लिए जूझ रहे पक्षकारों को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक व अनावश्यक रूप से हो रहे खर्चों को देखते हुवे लोक अदालत शिविरों की शुरुआत की गई। जिसे उम्मीद से अधिक सफलता मिल रही है इसके पीछे निःशुल्क, त्वरित समाधान व विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका है। एडीजे वंदना देवांगन ने आगे बताया कि लोक अदालत व न्यायालय सिर्फ न्यायालय भवन तक सीमित नहीं है बल्कि वे सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सकारात्मक सोच रखते हैं। उनकी मंशा है कि नगर या क्षेत्र में अनाथ व विक्षिप्त तरीके से घूम व रहने वाले लोगों की भी सामाजिक स्तर पर उन्हें सहयोग किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भी सामाजिक स्तर पर जीवन जीने का लाभ मिल सके ।

वहीं गरीब व निर्धन युवतियां जिनका विवाह इन कारणों से नहीं हो पा रहा है उनका भी सहयोग सामाजिक संस्थाओ के माध्यम से किया जाना चाहिए। ज्ञातव्य हो कि आगामी 9 मई को न्यायालय भवन में लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके व आपसी समझौते के तहत प्रकरणों का समाधान किया सके इस हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार, वर्षों से लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणो एवं प्री-लिटिगेशन चरण के प्रकरणों में अधिक से अधिक प्रकरणों का निष्पादन को लेकर एडीजे द्वारा बैठकों व तैयारियों हेतु बैठक की जा रही है। बैठकों में उपस्थित सभी को सम्बोधित करते हुए कहा की 09 मई को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में अधिवक्ताओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अपने सुलहनीय वादों में से कम से कम एक-एक वाद का निष्पादन अवश्य कराएं।

बैठक में सभी संबंधितों पक्षकारों व अधिवक्ताओं से राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर प्रकरण के पक्षकारों से आपसी समझौता नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपसी विवाद के मामले, व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, जिला न्यायालय में वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों एवं बैंक ऋण, विद्युत, जल के बकाया देयकों आदि संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण रखे जाएगें।

संक्षिप्त समाचार

ऑपरेशन तलाश के तहत दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। जिले में महिला संबंधी अपराधों पर सख्त कार्रवाई करते हुए रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत दुष्कर्म के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी भोजराम यादव को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला 31 मार्च 2026 को दर्ज किया गया था, जब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की एक महिला ने थाना कोतवाली में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि जनवरी 2026 में उसकी पहचान ग्राम बरदुला निवासी भोजराम यादव से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बने। पीड़िता के अनुसार 16 जनवरी को आरोपी उसे जन्मदिन के बहाने रायगढ़ लेकर आया, जहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने उसे काशीराम चौक बायपास रोड स्थित किराए के मकान में करीब 20 दिनों तक रखा और शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में 24 मार्च को आरोपी ने पीड़िता को उसके गांव वापस ले जाकर शादी से इनकार कर दिया और उसके साथ मारपीट करते हुए धमकी देकर छोड़ दिया। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 183/2026 धारा 69, 75(3), 115(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन तलाश के तहत कोतवाली पुलिस ने तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को ट्रेस कर गिरफ्तार किया। 23 अप्रैल को पुलिस टीम ने आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार किया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

बैगा बेटे ने की हत्या, मां करती थी तांत्रिक क्रिया का विरोध

रायपुर। जिले में बेटे ने हंसिए से अपनी ही मां को काट डाला। बताया जा रहा है कि झाड़-फूंक को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने गुस्से में आकर मां पर हंसिए से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कुआकोंडा थाना क्षेत्र का है। दरअसल, वारदात 23 अप्रैल 2026 की रात ग्राम धनीकरका में हुई है। शिकायतकर्ता कोवा मरकाम ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी आयते मरकाम और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर के आंगन में बैठे थे और आम छील रहे थे। उसी दौरान उसका बेटा बुधराम मरकाम अपनी बुआ के लिए झाड़-फूंक करने लगा। बताया गया कि झाड़-फूंक के दौरान उसने अपने पिता को देवगुड़ी से रेत लाने के लिए भेजा। इसी बीच रात करीब 10 बजे उसकी मां आयते मरकाम ने उसे झाड़-फूंक करने से मना किया और इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर बुधराम मरकाम गुस्से में आ गया। उसने अपनी मां के साथ मारपीट की और उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद पास में रखे हंसिए से उसके सीने में वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से आयते मरकाम (53) की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही कुआकोंडा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। कोवा की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 17/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया। टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने आरोप बुधराम मरकाम (34), निवासी ग्राम धनीकरका को 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना को स्वीकार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 25 अप्रैल 2026 को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर उसे जिला जेल दंतेवाड़ा भेज दिया गया है।

बस्तर में विदेशी फंडिंग पर ईडी की सख्ती, 153 संस्थाएं जांच के दायरे में, करोड़ों के लेन-देन की पड़ताल तेज

रायपुर। माओवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र में कथित मतांतरण गतिविधियों से जुड़े विदेशी फंडिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने ऐसी 153 संस्थाओं को जांच के घेरे में लिया है, जिन्हें विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी। जांच में यह सामने आया है कि अमेरिकी मिशनरी संस्था से जुड़े खातों से बस्तर और धमतरी क्षेत्र में करीब साढ़े छह करोड़ रुपये एटीएम के माध्यम से निकाले गए। इसके बाद अन्य संबंधित संस्थाओं के वित्तीय लेन-देन की भी बारीकी से जांच की जा रही है, जिन पर विदेशी धन के दुरुपयोग का संदेह है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ संस्थाओं पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में प्रलोभन देकर मतांतरण कराने के लिए विदेशी राशि का उपयोग किया। इस मामले के सामने आने के बाद विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठनों की निगरानी कड़ी कर दी गई है। आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 तक प्रदेश में 364 गैर-सरकारी संगठन सक्रिय थे। जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोक दी गई है, जबकि 127 संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जा चुका है। राज्य के गृह विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई । रिपोर्ट के आधार पर पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अब ईडी इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है।

तेंदुवा धाम में श्रीराम कथा का भव्य शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिया साधु संतों का आशीर्वाद

■ छत्तीसगढ़ धान का कटोरा होने के साथ-साथ सेवा, समर्पण और आस्था की भूमि - मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण स्थित राम मिलेंगे आश्रम, तेंदुवा धाम कुरियारी में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा में शामिल हुए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ आश्रम पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि सदैव भगवान श्रीराम के चरणों से धन्य रही है। उन्होंने वनवास काल में भगवान श्रीराम के आगमन और माता शबरी की अद्भुत भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि इस धरती ने आस्था, समर्पण और विश्वास की अनूठी परंपरा को सहेज कर रखा है। उन्होंने कहा कि तेंदुवाधाम आज धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु एक साथ श्रीराम कथा का श्रवण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को अत्यंत सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि एक ही मंच से अनेक संतों का सान्निध्य और आशीर्वाद प्राप्त होना विशेष अनुभव है। उन्होंने आश्रम परिसर में हरिवंश औषधालय एवं पंचकर्म केंद्र, श्री राम-जानकी मंडपम, हरिवंश वैदिक पाठशाला, मां दुर्गा गौ मंदिर और हनुमत प्रवेश द्वार सहित विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों के लोकार्पण पर आश्रम प्रबंधन और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा होने के साथ-साथ सेवा, समर्पण और आस्था की भूमि भी है। उन्होंने अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण के दौरान छत्तीसगढ़ से 11 ट्रक चावल और

चिकित्सकों की टीम के वहां पहुंचने का उल्लेख करते हुए इसे प्रदेशवासियों की गहरी श्रद्धा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि लगभग 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्रीराम भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, जो देश की सांस्कृतिक एकता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्रीरामलला दर्शन योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु अयोध्या धाम के दर्शन कर लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और जवानों के अदम्य साहस से आज प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है तथा राज्य में शांति, विकास और सामाजिक समरसता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया यहां की संस्कृति और जीवन मूल्यों की सच्ची पहचान है। इस अवसर पर परमपूज्य वासुदेवनंद सरस्वती महाराज, किन्नर अखाड़ा प्रमुख मां टीना सहित अनेक संत-महात्माओं की गरिमामयी उपस्थिति में विभिन्न धार्मिक-सांस्कृतिक परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। राघव सेवा समिति के प्रमुख डॉ. अशोक हरिवंश ने बताया कि यह स्थल माता शबरी की जन्मभूमि शिवरीनारायण में स्थित है, जहां 'कलिंग शैली' में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आश्रम में औषधालय, वैदिक विद्यालय, गौ मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, गीता वाटिका, शबरी रसोई और निर्धन कन्या विवाह जैसी अनेक सामाजिक-धार्मिक पहल संचालित हो रही हैं। कार्यक्रम के तहत विभिन्न वर्गों - दिव्यांगजन, रक्तदाता, कुष्ठ रोगी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों - को समर्पित विशेष दिवस भी आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, महंत श्री रामसुंदर दास सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

शादी का झांसा बना जाल आरोपी रायपुर से गिरफ्तार

रायपुर। संवाददाता

ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर शुरू हुई पहचान जब शादी के वादों में उलझी और फिर शोषण में बदल गई, तो तमनार पुलिस की तेज कार्रवाई ने आरोपी को रायपुर से दबोचकर जेल पहुंचा दिया, 26 अप्रैल 2026 को सामने आए इस मामले ने एक बार फिर भरोसे के नाम पर हो रहे अपराध का चेहरा उजागर किया, 33 वर्षीय युवती ने 23 अप्रैल को थाना तमनार में शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2023 में उसकी पहचान एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लखन कुमार पटनायक से हुई, जिसने खुद को रेलवे में जेई बताकर शादी का भरोसा दिलाया, बातचीत बढ़ी, विश्वास गहराया और आरोपी लगातार विवाह का आश्वासन देता रहा, फिर 14 दिसंबर 2025 को वह तमनार स्थित युवती के घर पहुंचा, जहां परिजनों के बाहर होने का फायदा उठाकर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया, इसके बाद भी वह शादी का लालच देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, जब परिवार ने सगाई और विवाह की बात आगे बढ़ाई तो आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी, सामाजिक रीति-रिवाज से विवाह से पीछे हटते हुए कोर्ट मैरिज का बहाना बनाया, मार्च 2026 में कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन भी कराया लेकिन इसके बाद अचानक संपर्क तोड़ दिया और साफतौर पर शादी से इंकार कर दिया, शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव ने अपराध क्रमांक 82/2026 के तहत की धारा 69 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की, एसएसपी के निर्देशन में टीम गठित हुई, तकनीकी और भौतिक सूचना के आधार पर पुलिस टीम रायपुर रवाना हुई और आरोपी लखन कुमार पटनायक, उम्र 37 वर्ष, निवासी भिलाईनगर जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया, आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया, इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी, एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रशांत राव, महिला प्रधान आरक्षक सुदो भगत, हेम प्रकाश सोन, आरक्षक पुरुषोत्तम सिदार और अतुल सिदार की अहम भूमिका रही।

दीपक बैज को नारी शक्ति के भावनात्मक पहलुओं का ज्ञान नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयानों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि नारी वंदन अधिनियम का लोकसभा में कांग्रेस यदि समर्थन करती तो आज परिस्थितियां कुछ और होतीं, लेकिन कांग्रेस ने इस बिल का विरोध कर मातृ शक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और अब जले पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कर रहे हैं। प्रदेश के केबिनेट मंत्री कश्यप ने कहा कि जिस तरह से विशेष सत्र को लेकर बैज का बयान आया है, वह बेहद ही निंदनीय है। हम विधानसभा में मातृ भावनाओं के मुताबिक मुद्दे पर चर्चा कर मातृ शक्ति की हितों की रक्षा को लेकर संकल्प लेंगे।

मन की बात हम सभी के लिए प्रेरणादायक

टिफिन मीटिंग में दिखी संगठन की आत्मीयता और एकजुटता

रायपुर। संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने को बूथ क्रमांक 203, क्लब हाउस, विनायक सिटी, भाठागांव रायपुर में मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण का श्रवण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, भाजपा प्रदेश मंत्री अमित साहू, विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, जिला अध्यक्ष रायपुर शहर रमेश सिंह ठाकुर, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित आमजन ने भी मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। मन की बात का प्रसारण सुनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में काले हिरण के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों का विशेष उल्लेख करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साय ने कहा कि यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे राज्य में काले हिरणों के संरक्षण की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना की है। प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देशवासियों को हर महीने के अंतिम रविवार का बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रधानमंत्री एक 'परिवार के मुखिया' की भांति 140 करोड़ भारतीयों से जुड़ते हैं और देश के विभिन्न कोनों में हो रहे नवाचारों को साझा करते हैं, जिससे आम जनता को प्रोत्साहन मिलता है। साय ने प्रधानमंत्री द्वारा बांस को 'पेड़' की श्रेणी से हटाकर 'घास' की श्रेणी में लाने के निर्णय की चर्चा की।जिससे अब बांस की कटाई, परिवहन और बिक्री में सुगमता होगी।

नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ कार में दरिंदगी की...

रायपुर। संवाददाता

नौकरी दिलाने का लालच देकर महिला और नाबालिग को जाल में फंसाने वाले शातिर की चाल आखिरकार पुलिस के सामने टिक नहीं पाई और घरघोड़ा पुलिस ने उसे उसकी कार समेत दबोचकर जेल पहुंचा दिया, मामला 26 अप्रैल 2026 का है जब पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि कैसे एक फोन कॉल से शुरू हुआ झांसा सुनसान रास्ते तक पहुंचा और फिर छेड़खानी में बदल गया, पीड़िता की 15 वर्षीय नाबालिग ने 24 अप्रैल को थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भाभी को 16 अप्रैल को एक अज्ञात युवक ने मोबाइल पर कॉल कर खुद को विजय बताते हुए रायगढ़ की कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा दिया, भरोसा जीतने के बाद 22 अप्रैल को उसी नंबर से दोबारा कॉल कर ग्राम अमलीडीह घरघोड़ा बुलाया गया, शाम करीब 5:30 बजे से शुरू हुआ यह सफर रात 8 बजे चिमटापानी पहुंचा जहां आरोपी खुद सामने आया और दोनों को अपनी ग्रे रंग की कार में बैठाकर सुनसान जगह ले गया, कार में बैठते ही उसका असली चेहरा सामने आया, पहले महिला के साथ गलत नियत से छेड़खानी की गई और विरोध करने पर नाबालिग के साथ भी जबरदस्ती की कोशिश की गई, डर और दहशत का माहौल बनाकर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया, लेकिन यह मामला यहीं नहीं रुका, थाना घरघोड़ा पुलिस ने अपराध क्रमांक 144/2026 के तहत एक्ट की धारा 8 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की, थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने तकनीकी जांच का सहारा लिया, मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया और आरोपी की पहचान रायकेरा निवासी सुरेन्द्र बेहरा के रूप में हुई, इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए दबिश दी और आरोपी को उसकी मारुति ब्रेजा कार क्रमांक छ॥-17-क-2761 सहित पकड़ लिया, पीड़िताओं के सामने शिनाख्त कराई गई जहां आरोपी की पहचान पक्की हुई, पूछताछ में उसने फर्जी नाम विजय बताकर नौकरी के बहाने बुलाने और अपराध करना कबूल किया, पुलिस ने मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ीं और आरोपी के पास से मोटोरोला मोबाइल फोन व घटना में इस्तेमाल कार जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

आर्थिक तंगी से रंजना की छुटी पढ़ाई, उपमुख्यमंत्री शर्मा के सहयोग से फिर होगी शुरू

रायपुर। कबीरधाम जिले में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने आर्थिक सहायता प्रदान कर एक प्रेरणादायक पहल की है। उन्होंने जरूरतमंद छात्राओं की पढ़ाई में सहयोग करते हुए ग्राम हरमो निवासी भारती साहू को 2 लाख रुपए तथा ग्राम चिल्फी निवासी रंजना झारिया को 25 हजार रुपए की राशि प्रदान की। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर उक्त राशि के चेक प्रदान किए गए। इस अवसर पर श्री नरेन्द्र मानिकपुरी, श्री अमर कुर्रे, श्री ओमकार साहू, श्री लोकचंद साहू, श्री मिलू साहू उपस्थित रहे। इस दौरान रंजना झारिया ने बताया कि उनके पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। उन्होंने कहा कि जब उन्हें जानकारी मिली कि उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तब उन्होंने उनसे संपर्क कर अपनी समस्या बताई। उनकी स्थिति को समझते हुए श्री शर्मा ने 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। रंजना ने बताया कि इस सहायता से वह अब दोबारा नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर सकेंगी और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगी।

मनरेगा श्रमिकों की ई केवायसी में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल रहा.....

■ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान

रायपुर/ संवाददाता

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों के ई-के वाय सी कार्य में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 97.11 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई-के वाय सी पूर्ण कर लिया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ ने केरलम, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों तथा कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को भी पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ;मनरेगा के तहत श्रमिकों की ई.केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में छत्तीसगढ़ ने देश भर में अग्रणी स्थान हासिल किया है। प्रदेश में लगभग 56.87 लाख से ज्यादा मजदूरों की डिजिटल वेरिफिकेशन पूरी की गई है जो भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह डिजिटल प्रक्रिया फर्जी जॉब कार्डों को हटाने और सीधे वास्तविक लाभार्थियों के बैंक खातों में मजदूरी पहुंचाने में मदद कर रही है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के सतत नेतृत्व, मॉनिटरिंग और प्रभावी रणनीति का परिणाम है। राज्य में योजनाबद्ध ढंग से अभियान चलाकर ई-के वाय सी की प्रक्रिया को तेज किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को समयबद्ध रूप से इससे जोड़ा जा सका। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 58 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिकों में से 56 लाख से अधिक का ई-के वाय सी सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीब और श्रमिक वर्ग के हितों के संरक्षण एवं उन्हें योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-के वाय सी के माध्यम से श्रमिकों को समय पर भुगतान एवं योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित हो रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम स्तर पर कार्यरत टीमों के समन्वित प्रयास का परिणाम है। उन्होंने बताया कि ई-के वाय सी से न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगी है, बल्कि वास्तविक हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने में भी पारदर्शिता आई है।

बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और ग्रामीणों को सीधा मिलेगा लाभ

दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगी बेहतर सुविधाएं-जलवायु मंत्री केदार कश्यप..

■ वन मंत्री ने किया 1.55 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण

रायपुर/ संवाददाता

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही है। उन्होंने बताया कि इन कार्यों से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, डिजिटल सेवाएं और सामुदायिक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार गांव, गरीब और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के संकल्प को निरंतर साकार कर रही है। इसी कड़ी में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के सिवनी में लगभग एक करोड़ 55 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। लोकार्पित कार्यक्रम के तहत सिवनी से खालेपारा तक 0.55 किमी सड़क (73.30 लाख रुपए) तथा सिवनी से आमागुड़ापारा तक 0.55 किमी सड़क (55.18 लाख रुपए) का निर्माण किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ग्राम बड़ेआमाबाल एवं बड़ेअलनार में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाएं और शासकीय योजनाओं का लाभ गांव में ही मिल सकेगा। शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनारपाल में प्रार्थना शेड का निर्माण भी किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। सोनारपाल में गणेश मंडली के पास शेड, टाइल्स एवं लाइट सहित निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इसके साथ ही ग्राम बड़ेआमाबाल के खरियापारा में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया गया, जो ग्रामीणों के सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र बनेगा।

संपादकीय

सियासत के फेर में फंसा महिला आरक्षण का हक

किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर सकी। इसमें कोई दोराय नहीं कि विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार और सभी विपक्षी दलों को एक ईमानदार इच्छाशक्ति के साथ काम करना चाहिए। मगर यही मुद्दा जब राजनीतिक लाभ उठाने का जरिया बनने लगता है, तब इस पर सवाल उठने लगते हैं। बीते हफ्ते सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन जरूरी समर्थन न मिल पाने की वजह से वह लोकसभा में गिर गया।गौरतलब है कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर सकी। हालांकि इस बार परिसीमन विधेयक में संशोधन के लिए जिस तरह महिला आरक्षण का मसला भी जुड़ा हुआ था, उसमें इस मुद्दे पर दो-तिहाई सांसदों को अपने पक्ष में खड़ा कर पाना सरकार के लिए मुश्किल था। यानी पहले ही यह माना जा रहा था कि लोकसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसके बावजूद यह विचित्र है कि सरकार ने इस पर जोर-आजमाइश करने की कोशिश की।दरअसल, इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य यह बताया गया था कि इससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही, 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर राज्यों में सीटों के परिसीमन की इजाजत दी जाएगी और लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी। मगर चूंकि परिसीमन के साथ उलझे इस मुद्दे पर सरकार को जरूरी संख्या बल का समर्थन नहीं मिल सका, इसलिए अब भाजपा विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान यह आरोप लगाने की कोशिश कर सकती है कि विपक्षी पार्टियां महिलाओं को भागीदारी देने का समर्थन नहीं करतीं। सवाल है कि महिलाओं की विधायिका में आरक्षण से संबंधित जो विधेयक वर्ष 2023 में ही पारित होकर संविधान का हिस्सा बन चुका था, उसे फिर से तब क्यों लाया गया, जब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। यह बेवजह नहीं है कि इस संशोधन विधेयक को लाए जाने के समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।ऐसा लगता है कि इस विधेयक की जटिलता और उसके पारित होने के सामने खड़ी चुनौतियों की तस्वीर चूंकि लगभग साफ थी, इसलिए इसे राज्यों में जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच महिलाओं का समर्थन हासिल करने वाले एक अहम मुद्दे के रूप में भी देखा गया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन में भी यह साफ दिखा, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़े इस संशोधन विधेयक के पारित न होने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार बताया।मगर विधेयक में जिस तरह सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को नए परिसीमन और लोकसभा के विस्तार के ढांचे से जोड़कर पेश किया था, उसमें वह किस तरह के समर्थन की उम्मीद कर रही थी। महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ-साथ खासतौर पर परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के राज्यों की जैसी प्रतिक्रिया थी, उसमें विपक्षी दलों के समर्थन या विरोध की तस्वीर एक तरह से पहले से साफ थी।

राजनीति में महिलाओं की राह मुश्किल, क्या आरक्षण बनेगा पितृसत्ता को तोड़ने का निर्णायक हथियार?

जनतंत्र में गजब की ताकत होती है। यह चीजों को विद्युत गति से उलट-पुलट कर देने की क्षमता रखता है। इसी क्षमता के कारण यह मुरझा तो सकता है, पर कभी मरता नहीं है। यह सिर्फ चुनाव की पद्धति या प्रशासन का तरीका मात्र नहीं है, बल्कि गैरबराबरी को समाप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। यही कारण है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने उन्हें 'मैं भी हूं' और 'मैं भी कर सकती हूं' का अहसास कराया। वोट तो पहले भी दे रही थीं, पर उनमें नेतृत्व करने का आत्मविश्वास अंकुरित नहीं हो पाया था। आरक्षण ने शिक्षित-अशिक्षित, गरीब-अमीर, सामंती सोच आदि की दीवारों को एक झटके में तोड़ दिया। आज हजारों की संख्या में महिला सरपंच हैं और अन्य स्थानीय निकायों में उनकी उपस्थिति है। महिला चेतना तब परिवार की राय के अधीन थी, अब नीतियों के निर्धारण, विकास के कार्यक्रमों और सार्वजनिक गतिविधियों में सशक्त हिस्सेदारी देखी जा रही है।

(राकेश सिन्हा)

लोकतंत्र का मूल भाव योग्यता की खोज और नेतृत्व की पात्रता का सृजन करना होता है। इसके इतर होने पर जाति धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा की संकीर्ण भूमिका बढ़ने लगती है।

एक समय वह था और एक समय यह है। वर्षों पूर्व स्कूल की छुट्टी में जब मैं शहर से गांव गया तब एक कैलेंडर मेरे पास था। उसमें गाड़ी चलाती हुई एक महिला की तस्वीर थी। मेरे पड़ोस की एक नवविवाहिता, जो घूंघट में थी, उसे देखकर विस्मय कर रही थी। समय बीता। कुछ वर्ष पूर्व गांव में जब था, तो वही महिला स्थानीय निकाय की उम्मीदवार थी और अपने लिए घर-घर जाकर वोट मांग रही थी। उन्हें देखकर पुरानी बातें मेरे स्मृति-पटल पर उभर कर सामने आ गईं।

जनतंत्र में गजब की ताकत होती है। यह चीजों को विद्युत गति से उलट-पुलट कर देने की क्षमता रखता है। इसी क्षमता के कारण यह मुरझा तो सकता है, पर कभी मरता नहीं है। यह सिर्फ चुनाव की पद्धति या प्रशासन का तरीका मात्र नहीं है, बल्कि गैरबराबरी को समाप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। यही कारण है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने उन्हें 'मैं भी हूं' और 'मैं भी कर सकती हूं' का अहसास कराया। वोट तो पहले भी दे रही थीं, पर उनमें नेतृत्व करने का आत्मविश्वास अंकुरित नहीं हो पाया था। आरक्षण ने शिक्षित-अशिक्षित, गरीब-अमीर, सामंती सोच आदि की दीवारों को एक झटके में तोड़ दिया। आज हजारों की संख्या में महिला सरपंच हैं और अन्य स्थानीय निकायों में उनकी उपस्थिति है। महिला चेतना तब परिवार की राय के अधीन थी, अब नीतियों के निर्धारण, विकास के कार्यक्रमों और सार्वजनिक गतिविधियों में सशक्त हिस्सेदारी देखी जा रही है।

इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला आरक्षण का आग्रह चेतना को स्थानीयता के पिंजरे से बाहर निकालकर उसे राष्ट्रीय क्षितिज पर लाने का उपक्रम है। यों महिलाओं की भागीदारी पहले भी रही है। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहीं। संविधान सभा की सभी पंद्रह महिलाएं पूर्णिमा बनर्जी से लेकर एन्नी मास्करेने तक की पृष्ठभूमि कुलीन थी। जमीनी प्रतिनिधित्व का विषय तब मस्तिष्क में भी नहीं था। इसलिए आम महिला की चेतना को इस संक्षिप्त और सांकेतिक भागीदारियों से जगाया नहीं जा सका।

राजनीति में प्रवेश, पुरुषों के लिए सामान्य बात ही नहीं, उनका 'पुरुषार्थ' माना जाता है, तो महिलाओं के लिए यह जोखिम उठाने वाला हो जाता है। इसलिए भागीदारी प्राप्त करने में उन्हें अनेक बाधाओं को पार करना होता है। लोकसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान राजनीति में व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच और प्रभाव को सदा के लिए दफनाने वाला सुधारवादी से कहीं अधिक क्रांतिकारी कदम हो सकता है।

यह सिर्फ कुछ सौ महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जमीन पर हर तबके तथा हर वर्ग की महिलाओं को राजनीतिक विमर्श से जोड़ेगा। वे अब तक विमर्श की पात्र रही हैं, अब वे विमर्श में भागीदार बन रही हैं। महिला सम्मान और अस्तित्व, दोनों ही लंबे समय से विमर्श और सुधारवाद का हिस्सा रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि समाज सुधार के प्रश्न पर विरोध के दो ध्रुवों के बीच भी एकता अनैतिक नहीं मानी जाती है। 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में राष्ट्रवादी राजा राममोहन राय और साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल बेंटिकट के बीच पूर्ण सहमति थी।

भारत के सुधारकों ने 1921 की जनगणना में अभिव्यक्त तल्ख सच को समाज की अपनी आलोचना से कहीं अधिक समाज के लिए चुनौती और अवसर के रूप में देखा। उसमें रहस्योद्घाटन हुआ था कि शून्य से एक वर्ष की 597, एक से दो वर्ष के बीच के 494 नवजात शिशुओं को विधवा घोषित कर दिया गया था। यह संख्या बढ़ती गई। इस जनगणना की रपट ने स्वामी श्रद्धानंद सहित अनेक राजनीतिकों को गहन समाज सुधार के लिए प्रेरित किया था। उस सच से इस सच तक पहुंचने में समाज ने अनेक प्रयासों और सुधारों का साक्षात्कार किया है। महिला आरक्षण पर उत्तर-दक्षिण विभाजन का मुद्दा बेमानी है। भौगोलिक संरचना से भारतीय राज्य, समाज और लोकतंत्र अप्रभावित है। राष्ट्र एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई है, जो मनुष्य शरीर की तरह है। यह यांत्रिक नहीं है। जिस तरह से शरीर का प्रत्येक अंग जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह मेघालय से मध्य प्रदेश और अरुणाचल से आंध्र प्रदेश राष्ट्र, समाज और राजनीति का प्रतिस्पर्द्धी या विरोधाभासी इकाइयां नहीं हैं। ऐसा होना भारत में संभव नहीं है। हमारी राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक कारणों से अविभाज्य है। क्षेत्रीय अस्मिता को लोकतंत्र पर आरोपित करने का प्रयास लोकशाही के मूल अर्थ को खो देने जैसा है। संसद मूलत- कानून और कार्यपालिका के लिए जिम्मेदार एक संप्रभु संरचना है। एक सांसद जितना अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि है, उससे अधिक उसकी राष्ट्रीय पहचान होती है।

लोकतंत्र का मूल भाव योग्यता की खोज और नेतृत्व की पात्रता का सृजन करना होता है। इसके इतर होने पर जाति धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा की संकीर्ण भूमिका बढ़ने लगती है। पर यह जनतंत्र उसे धारण करने वालों में अपूर्णता का संकेत है। जिस समाज में राजनीति और जनता के बीच में गैर चुनावी, पर राजनीतिक रूप से सक्रिय पात्रों, संगठनों और सुधारकों की अल्पता होती है, वहां प्रतिस्पर्धी राजनीति बेलगाम हो जाती है। एक समय विनोबा भावे, जयप्रकाश, सिद्धराज ढड्ढा, वीएम तारकुंडे जैसे लोग थे। वे चुनाव नहीं लड़ते थे, पर चुनावी राजनीति पर अंकुश की तरह होते थे।

महिला आरक्षण उसी योग्यता के सृजन का सशक्त माध्यम है। प्रश्न क्यों जरूरी है, उसे एक प्रचलित परंपरा से समझा जा सकता है। मेघालय की खासी जनजाति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की प्रधानता है, पर जब राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न आता है, तब उनकी अपनी परंपरागत राजनीतिक संस्था 'दरबार' में यह पूरी तरह प्रतिबंधित है। भले ही यह लोकसभा में अंकगणित के चक्रव्यूह में फंस गया, पर इससे उपजने वाला विमर्श हमें मैत्रेयी-गार्गी तक पहुंचाने की क्षमता रखता है।

भारत में क्यों बढ़ रहा लीवर डैमेज का खतरा?

इन 7 संकेतों को न करें नजरअंदाज

(दिव्यांशी भदौरिया)

वर्ल्ड लिवर डे पर जानें लिवर खराब होने के 7 प्रमुख लक्षण। यदि आपको लगातार थकान, त्वचा का पीलापन, या पेट में सूजन जैसे संकेत दिखें, तो यह गंभीर लिवर समस्या का संकेत हो सकता है, जिसकी तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

आज यानी 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लिवर से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरुकता फैलाना, शुरुआती पहचान को बढ़ावा देना और लिवर के हेल्थ के लिए प्रति लोगों को सचेत करना है। इस साल की थीम है 'सॉलिड हैबिट्स, स्ट्रांग लिवर' जिसका मतलब है कि मजबूत आदतें, स्वस्थ लिवर है। भारत में लिवर की बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। सबसे डराने वाली बात तो यह है कि लिवर की बीमारी के लक्षण तब तक सामने नहीं आते, जब तक कि स्थिति बहुत गंभीर न हो जाए। इसी वजह से लिवर की बीमारियां जल्दी पता नहीं चलती है। हालांकि, कुछ संकेतों पर ध्यान देने से बीमारी का पता चल जाता है। आइए आपको इन संकेतों के बारे में बताते हैं।

लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना: अगर आपको सबसे ज्यादा थकान महसूस होती है तो इसका पहला संकेत यही होता है। जब लिवर ठीक से कम नहीं करता है, तो ब्लड में टॉक्सिंस जमा होने लगते हैं। इससे दिमाग की काम करने की क्षमता और शरीर की एनर्जी प्राभिवत होती है।

त्वचा और आंखों का पीला पड़ना: जब लिवर बिलीरुबिन को ठीक तरह से संभाल नहीं पाता, तो यह शरीर में इकट्ठा होने लगता है। इसके कारण त्वचा और आंखों में पीला रंग दिखाई देने लगता है, जिसे पीलिया का संकेत माना जाता है। आमतौर पर लोग इसी बदलाव को देखकर डॉक्टर से सलाह लेते हैं, लेकिन कई बार तब तक समस्या काफी गंभीर रूप ले चुकी होती है।

भूख में कमी और वजन का अचानक गिरना: अक्सर पाया जाता है कि लिवर खराब होने पर पाचन तंत्र पर सीधा असर दिखने लगता है। भारत की 9व से 32व आबादी फैटी लिवर से परेशान है। आज की जनरेशन में भी भूख लगने जैसे लक्षण आम होते जा रहे हैं, जो लिवर का समस्या का बड़ा संकेत है।

पेट में दर्द या सूजन ज्यादा जानें स्वास्थ्य फिटनेस

पेट में तरल पदार्थ का जमा होना इस बात का संकेत होता है कि लिवर बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। भारत में सिरोसिस के मामलों का एक बड़ा कारण अत्यधिक शराब का सेवन माना जाता है, जिसके चलते पेट फूलने और सूजन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं।

गहरे रंग का पेशाब और हल्का मल: यदि आपके पेशाब का रंग गहरा है और मल का रंग असामान्य रूप से हल्का है, तो यह बाइल के फ्लो में समस्या का संकेत हो सकता है। कई लोग इसे सिर्फ डिहाइड्रेशन समझकर इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में दिक्कत दे सकता है।

आसानी से चोट लगना या ब्लीडिंग होना: लिवर शरीर में खून को जमाने वाले जरूरी तत्व तैयार करता है। जब यह अंग कमजोर पड़ जाता है, तो छोटी-सी चोट लगने पर भी अधिक रक्तस्राव होने लगता है या शरीर पर आसानी से नीले निशान उभर आते हैं। कई शोधों के अनुसार, भारत में अनेक लोगों को सिरोसिस की जानकारी तब मिलती है, जब उन्हें खून बहने जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।

त्वचा पर खुजली होना: अगर बिना किसी रैशेज या दाने के शरीर पर खुजली होना लिवर की बीमारी का एक छिपा हुआ लक्षण हो सकता है। यह त्वचा के नीचे बाइल सॉल्ट्स जमा होने के कारण होता है, जिसे लोग अक्सर सामान्य त्वचा समझते हैं।

समय पर पहचान है जरूरी: आपको बता दें कि, लिवर अचानक से फेल नहीं होता बल्कि यह धीरे-धीरे खराब होता है और अक्सर इसमें दर्द भी नहीं होता है। इसलिए, समय रहते हुए लिवर की बीमारियों के लक्षणों की पहचान करना बेहद जरूरी है। इस लेख के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें।

चुनौतियों के चक्रव्यूह के बीच खड़ा बिहार का नया 'सम्राट'

सम्राट चौधरी का राजनीतिक उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह उनके पिता शकुनी चौधरी की विरासत, और उनके स्वयं के आक्रामक संघर्ष, दशकों की राजनीतिक यात्रा, रणनीतिक धैर्य और समयानुकूल निर्णयों का परिणाम है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में जन्मे सम्राट ने बहुत कम उम्र में ही सत्ता का स्वाद चख लिया था। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर वैचारिक बदलावों और रणनीतिक फैसलों से भरा रहा है।

(योगेश कुमार गोयल)

सम्राट चौधरी का राजनीतिक उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह उनके पिता शकुनी चौधरी की विरासत, और उनके स्वयं के आक्रामक संघर्ष, दशकों की राजनीतिक यात्रा, रणनीतिक धैर्य और समयानुकूल निर्णयों का परिणाम है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में जन्मे सम्राट ने बहुत कम उम्र में ही सत्ता का स्वाद चख लिया था।

बिहार की राजनीति में सत्ता का शिखर छूना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है उस शिखर पर टिके रहकर अपनी सर्वमान्यता सिद्ध करना। सम्राट चौधरी का बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में उदय राज्य के सियासी इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात माना जा रहा है। यह केवल एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में उस 'बड़े भाई' की भूमिका को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना है, जिसका इंतजार पार्टी कार्यकर्ता दशकों से कर रहे थे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य को भरने की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के कंधों पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह नीतीश कुमार की उस लंबी और गहरी छाया से बाहर निकल पाएंगे, जिसने पिछले दो दशकों से बिहार की राजनीति को परिभाषित किया है? यही वह कसौटी है, जिस पर अब सम्राट चौधरी को परखा जाएगा।

सम्राट चौधरी का राजनीतिक उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह उनके पिता शकुनी चौधरी की विरासत, और उनके स्वयं के आक्रामक संघर्ष, दशकों की राजनीतिक यात्रा, रणनीतिक धैर्य और समयानुकूल निर्णयों का परिणाम है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में जन्मे सम्राट ने बहुत कम उम्र में ही सत्ता का स्वाद चख लिया था। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर वैचारिक बदलावों और रणनीतिक फैसलों से भरा रहा है। राजद और जदयू जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ काम करने के बाद 2017 में भाजपा का दामन थामना उनके करियर का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। भाजपा ने उनमें एक ऐसे पिछड़ा नेतृत्व (ओबीसी) को देखा, जो न केवल संगठन में जान फूंक सकता था बल्कि राजद के 'माई' (एमवाई) समीकरण के

सामने एनडीए के 'लव-कुश' समीकरण को मजबूती दे सकता था। विशेषकर कुशवाहा समुदाय से आने के कारण सम्राट चौधरी भाजपा के लिए सामाजिक संतुलन का सबसे सटीक मोहरा साबित हुए। भाजपा ने उन्हें न केवल स्वीकार किया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद देकर उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा भी जताया। यही भरोसा आज उन्हें मुख्यमंत्री पद तक ले आया है।

मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की नियुक्ति के साथ ही बिहार की राजनीति में एक दुर्लभ संयोग भी जुड़ा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद वह दूसरे ऐसे नेता बने हैं, जिन्होंने पहले उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली और बाद में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। यह उपलब्धि उनके कद को तो बढ़ाती है लेकिन इसके साथ आने वाली अपेक्षाएं उनके लिए हिमालयी चुनौतियों जैसी हैं। नीतीश कुमार केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि वह बिहार के लिए एक 'इंस्टीट्यूशन' बन चुके थे। उनके 20 वर्षों के शासनकाल ने राज्य में सुशासन की एक ऐसी परिभाषा गढ़ी, जिसमें महिला सुरक्षा, सड़कें, बिजली और शराबबंदी जैसे मुद्दे हर घर से जुड़े थे। सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वे स्वयं को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में पेश करते हैं या एक ऐसी नई पहचान गढ़ते हैं, जो नीतीश के 'विकास' और भाजपा की 'वैचारिक प्रखरता' का संगम हो।

अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर एकमत हैं कि नीतीश कुमार जैसा सर्वमान्य नेता बनना सम्राट चौधरी के लिए रातों-रात संभव नहीं होगा। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता समाज के हर वर्ग, चाहे वह महादलित हो, अति पिछड़ा हो या आधी आबादी (महिलाएं) हो, में गहराई तक थी। सम्राट चौधरी के पास फिलहाल एक मजबूत सांगठनिक ढांचा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है लेकिन उन्हें अपनी 'आक्रामक छवि' को अब 'प्रशासकीय संयम' में बदलना होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अब उनके हर फैसले की तुलना नीतीश कुमार के मानकों से की जाएगी। क्या वह उसी सहजता से महादलितों और अति पिछड़ों के हितों की रक्षा कर पाएंगे? क्या वह शराबबंदी जैसी पेचीदा नीतियों को लेकर जनता के बीच अपना स्पष्ट नजरिया रख पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका उत्तर उनके कार्यकाल के शुरुआती सौ दिन ही तय करेंगे। चुनौतियां केवल बाहर ही नहीं, गठबंधन के भीतर भी हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जदयू के भविष्य और निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में प्रवेश ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है। जदयू के भीतर इस बदलाव को लेकर एक दबी हुई छटपटाहट है। सम्राट चौधरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि गठबंधन के सहयोगी दल खुद को उपेक्षित महसूस न करें। साथ ही, उन्हें भाजपा के भीतर भी उन वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेना होगा, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पीछे रह गए। सम्राट चौधरी पर उनके पुराने विवादों, जैसे कम उम्र में मंत्री पद से हटाए जाने की घटना और उनके शैक्षणिक पहलुओं को लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा। एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पेशेवर छवि और शुचिता पर उठने वाले सवालों का सामना उन्हें अपनी कार्यशैली से ही करना होगा। बिहार में 2025 का जनादेश एक तरह से 'फेयरवेल मैंडेट' जैसा रहा है, जहां जनता बदलाव की मानसिक तैयारी कर चुकी थी। सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी ताकत उनका ओबीसी समुदाय से होना और भाजपा आलाकमान का पूर्ण समर्थन है लेकिन उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा 'नीतीश कुमार का औरा' है। भाजपा ने अब तक बिहार में नीतीश कुमार के साये में राजनीति की है, अब उसे अपनी स्वतंत्र इमारत खड़ी करनी है, जिसकी नींव सम्राट चौधरी को रखनी है। यह सफर कांटों भरा है क्योंकि उन्हें न केवल विकास की रफ्तार बनाए रखनी है बल्कि बिहार की उस जटिल सामाजिक संरचना को भी साधे रखना है, जहां जाति की राजनीति कभी खत्म नहीं होती। सम्राट चौधरी की कहानी एक ऐसे संघर्षशील नेता की है, जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने जा रही है। क्या वे बिहार को 'बीमारू' छवि से पूर्णतः मुक्त कर 'विकसित बिहार' के संकल्प को सिद्ध कर पाएंगे? यह भविष्य के गर्भ में है मगर फिलहाल बिहार की सत्ता का यह नया 'सम्राट' चुनौतियों के चक्रव्यूह के बीच खड़ा है। सम्राट चौधरी के पास अवसर भी है और चुनौती भी, अब यह उनके नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि वे इस अवसर को इतिहास में कैसे दर्ज कराते हैं।

(लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और 'सागर से अंतरिक्ष तक- भारत की रक्षा क्रांति' सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन

सुकमा। गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत समस्त नगरवासियों एवं संत समाज द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। अभियान के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ,राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम सुकमा जिले के प्रत्येक तहसील में ज्ञापन गई है। यह ज्ञापन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से भेजा जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियान से जुड़े लोगों ने तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर को संबोधित एक आवेदन पत्र तैयार किया है, जिसमें भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन में गौवंश के महत्व को रेखांकित किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि गाय न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संतुलन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से ठोस नीति बनाने तथा जनजागरूकता बढ़ाने की मांग की गई है। अभियान से जुड़े लोगों ने बताया कि यह ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ-साथ मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का उद्देश्य है, ताकि गौसंरक्षण के विषय में व्यापक स्तर पर विचार हो सके और आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। आवेदन पत्र में नगरवासियों, संत समाज और सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर भी शामिल हैं, जो इस अभियान के प्रति लोगों के समर्थन को दर्शाते हैं। अभियान के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे इस ज्ञापन को उच्च स्तर तक पहुंचाने में सहयोग करें और इस पुनीत कार्य में अपना मार्गदर्शन प्रदान करें।

सुकमा में सौंपे गए ज्ञापन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य अधिवक्ता दीपिका शोरी, विहिप के जिलाध्यक्ष अनिल टावरी, वनवासी कल्याण आश्रम के जंगईया, गुप्तेश्वर गंगबेर, वरिष्ठ पत्रकार लीलाधर राठी, भोमराज जैन,सत्यभामा गंगबेर,मालती भदौरिया, मनीषा शर्मा,राधे राधे पण्डित,फकीर महाराज ,नर्मदा मेडम ,मीना सिरसिया,बसंती यादव, राजकुमार लोहिया ,बीजू जैन,जागेश्वर साहू के साथ अनेकों नगरवासी उपस्थित रहे।

पेट्रोल पम्प से पैसा चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार

कोण्डागांव। 19 अप्रैल को चोरी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर थाना में अपराध क्रमांक 71/26 धारा 305, 331 (4) बीएनएस. के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीश्रीमाल के द्वारा तत्काल टीम गठित कर पार्टी आरोपी पता तलाश हेतु रवाना करने का निर्देश देने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्र एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशकाल अरुण नेताम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी को त्वरित दिशा निर्देश करते हुए चोरी की अज्ञात आरोपी का पता तलाश करने का निर्देशित करने से त्वरित कार्यवाही कर टीम रवाना किया गया। विवेचना दौरान पुलिस पार्टी के द्वारा अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया गया। पता तलाश दौरान तकनीकी संसाधनों के माध्यम से आरोपी गोपाल थापा उर्फ गोपाल साउत पिता जगत बहादुर उम्र 23 वर्ष निवासी शांति नगर जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. को तलब कर प्रकरण में चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा 16 अप्रैल के रात्रि 01: 00 से 02: 00 बजे के मध्य मुकेश पेट्रोल पम्प केशकाल के ऑफिस में घुसकर ड्राज में रखे 55,000/- रुपये एवं एक नग रियलमी कम्पनी का मोबाईल फोन को चोरी करना स्वीकार कर चोरी की रकम 9120 रुपये व एक नग रियलमी कम्पनी का मोबाईल को आरोपी के कब्जे से जब्त कर विधिवत 25 अप्रैल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय के आदेश पर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल जगदलपुर भेजी गयी। संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक विकास बघेल, उपनिरी. गुलाब टंडन, सउनि. रामकृष्णा जैन, प्रधान आरक्षक ईश्वर नेताम, आरक्षक अमित मंडावी एवं साइबर सेल कोंडागांव के आरक्षक जितेंद्र मरकाम आरक्षक बीजू यादव की अहम भूमिका रही है।

बनियागांव के पास हाईवे पर खड़ी ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत, पत्नी-बेटा गंभीर

कुछ देर बाद स्कॉर्पियो भी हादसे का शिकार

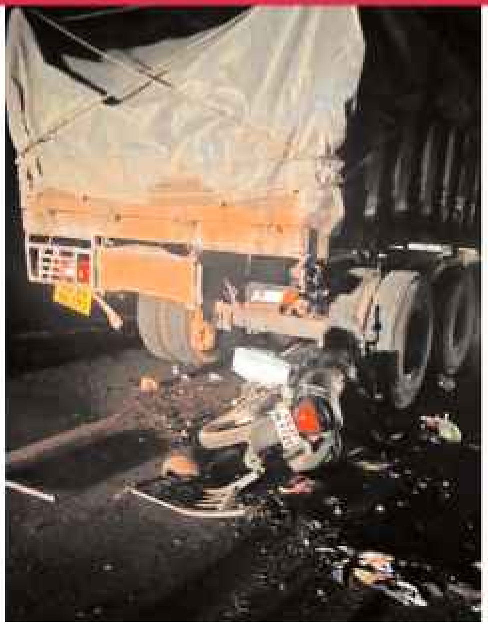

कोण्डागांव। सिटी कोतवाली कोण्डागांव अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर बनियागांव के पास रात खड़ी ट्रक से लगातार दो सड़क हादसे हो गए। पहले हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके कुछ देर बाद उसी खड़ी ट्रक से एक स्कॉर्पियो वाहन भी टकरा गया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। जानकारी के अनुसार, बाइक क्रमांक सीजी 27 एच 1725 में सवार पुसावंद गांव निवासी श्यामलाल बघेल (39) अपनी पत्नी धनई बघेल (25) और 5 वर्षीय पुत्र रियांशु के साथ बड़ेबेंदरी मेला से लौट रहे थे। इसी दौरान बनियागांव के पास उनकी बाइक सड़क पर खड़ी ट्रक क्रमांक सीजी 04 एमक्यो 2272 के पीछे जा घुसी। हादसे में श्यामलाल बघेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल कोण्डागांव लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पहले हादसे के कुछ समय बाद कांकेर से भैरमगढ़ लौट रही एक स्कॉर्पियो भी उसी खड़ी ट्रक से टकरा गई। वाहन में सवार पति-पत्नी और चालक मौजूद थे, जिनमें पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल कोण्डागांव लाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोंडागांव जिले को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के पश्चात जिले में शांति, सामान्य व्यवस्था एवं विकास कार्यों की नई शुरुआत हुई है

कोण्डागांव। पूर्व में नक्सली ऑपरेशन के दौरान जिले के जंगल, पहाड़ी एवं संवेदनशील क्षेत्रों में नक्सलियो के विरुद्ध सर्चिंग, घेराबंदी कार्यवाही हेतु सुरक्षा, छिपाव एवं रणनीतिक आवश्यकता के कारण कैमफ्लाज वर्दी का उपयोग कोंडागांव पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था। यह वर्दी ऑपरेशनल दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई थी और नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान में जिला नक्सल मुक्त हो जाने के कारण अब सामान्य पुलिसिंग, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसेवा के कार्यों को और अधिक पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अब कोंडागांव जिले में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यूटियों के दौरान खाकी वर्दी धारण कर रहे हैं। यह परिवर्तन जिले में शांति की स्थापना एवं सामान्य स्थिति की बहाली का स्पष्ट संदेश है। खाकी वर्दी पुलिस की पारंपरिक पहचान है जो जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क, विश्वास एवं सहयोग बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। इससे पुलिस बल अधिक सुलभ, पहचानने योग्य एवं जवाबदेह बनेगा। जिला पुलिस सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करती है। किसी भी प्रकार की सूचना, शिकायत अथवा सहायता हेतु नजदीकी थाना, कंट्रोल रूम अथवा नजदीकी थाना से संपर्क किया जा सकता है।

जगरगुण्डा में शिक्षा का नया हब, जावंगा मॉडल पर एजुकेशन सिटी की तैयारी

कोंटा। विकासखंड के जगरगुण्डा में एजुकेशन सिटी के निर्माण की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कलेक्टर अमित कुमार द्वारा अधिकारियों की विशेष टीम गठित की गई है, जो क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार करेगी। इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में गठित टीम ने दंतेवाड़ा जिले के जावंगा स्थित एजुकेशन सिटी का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया। सहायक आयुक्त हेमंत सिन्हा के नेतृत्व में टीम ने आस्था, गुरुकुल, सक्षम, डीएवी, आईटीआई, ऑडिटोरियम, मेस, एकलव्य खेल परिसर और कन्या शिक्षा परिसर सहित विभिन्न संस्थानों का दौरा कर शैक्षणिक, तकनीकी एवं प्रायोगिक सुविधाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण से प्राप्त जानकारियों के आधार पर अब जगरगुण्डा में एजुकेशन सिटी की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी। टीम में तहसीलदार योगेंद्र पात्रे, कार्यपालन अभियंता हिलोन ध्रुव, रविंद्र ताती, त्रिवेणीकांत गजेंद्र, एसडीओ गौरव सोनकिया, पीके प्रधानी एवं एपीसी आशीष राम शामिल रहे। यह परियोजना क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षा और विकास के नए अवसर खोलने वाली मानी जा रही है।

कोंटा महाविद्यालय में कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित, छात्रों को मिला प्रेरक मार्गदर्शन

कोंटा। शासकीय नवीन महाविद्यालय कोंटा में सोमवार को कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला 2026 का आयोजन किया गया। इसमें सामान्य प्रशासन, पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को करियर चयन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण व सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को सही दिशा देना, उनके भविष्य को संवारना और उन्हें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना रहा। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की, एसडीएम सुभाष शुक्ला, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रशांत देवांगन, जनपद सीईओ सुमित ध्रुव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए अनुशासन, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण और निरंतर अभ्यास की अहमियत बताई। साथ ही विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए, जिससे कार्यक्रम और अधिक प्रभावशाली व उपयोगी बना। इस दौरान एसडीएम सुभाष शुक्ला ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद मजबूत इरादों से सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों को असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ने और नियमित अध्ययन को आदत बनाने की सलाह दी। अंत में प्राचार्य सुरेश बाबू ने सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के बाद छात्रों में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला तथा इसे भविष्य निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया।

चंद घंटो मे कोण्डागांव पुलिस ने किया छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार

कोण्डागांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 26 अप्रैल को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह 25 अप्रैल को रात्रि में ग्राम बड़े बेंदरी का वार्षिक मेला देखने गयी थी। आरोपी डोनाल्ड बघेल के द्वारा पीड़िता को स्कूटी से घर छोड़ दूंगा बोल कर समय रात्रि करीबन 02.30 बजे अपने स्कूटी क्रमांक सीजी 27 एन 2609 से ले जाकर ग्राम बड़े बेन्दरी के नया पारा आम पेड़ के पास गाड़ी रोककर गलत नियत से जबरदस्ती पीड़िता के साथ छेड़छाड़ किया है कि रिपोर्ट पर आरोपी डोनाल्ड बघेल के विरुद्ध थाना कोण्डागांव में अपराध कायम कर विवेचना लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीश्रीमल (भा0पु0से0) के निर्देशानुसार एवं अति0 पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा के मार्गदर्शन में एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव रूपेश कुमार के पर्यवेक्षण में प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार करने थाना कोण्डागांव से टीम गठित किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी डोनाल्ड बघेल पिता जगदीश बघेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बडे बेन्दरी बायकापदर थाना कोंडागांव से घटना के संबंध मे पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार करने व आरोपी के विरूध्द अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 26/04/26 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ उपाध्याय, सहायक उप निरीक्षक शांति यादव, प्रधान आरक्षक अशोक मरकाम, म0 आर0 गायत्री शोरी, आर0 करण ध्रुव, विष्णु मरई का विशेष योगदान रहा।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु बीजापुर में विशेष टीकाकरण अभियान: 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी बालिकाओं को लगेगा एचपीवी का जीवन रक्षक टीका

बीजापुर। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर की पूर्ण रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक ऐतिहासिक और अहम कदम उठाया गया है। जिले की बेटियों को भविष्य में इस जानलेवा बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए विस्तृत HPV (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ और किसे लगेगा टीका- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर डॉ. बीआर पुजारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब बीजापुर जिले के विकासखंड स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC और जिला अस्पताल में HPV वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में यह टीका विशेष रूप से उन सभी लड़कियों को लगाया जा रहा है, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। यह सही उम्र है जब इस वैक्सीन का प्रभाव सबसे अधिक होता है और शरीर में कैंसर से लड़ने वाली मजबूत इम्युनिटी विकसित हो जाती है। क्यों जरूरी है यह टीका- आम जनता को जागरूक करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सर्वाइकल कैंसर की गंभीरता को स्पष्ट किया है। **देश में दूसरा सबसे बड़ा खतरा:-** सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है।

गंभीर स्थिति- भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर के लगभग 1,20,000 (1.2 लाख) नए मामले सामने आते हैं और करीब 77,000 महिलाओं की इससे मृत्यु हो जाती है। यानी देश में हर 8 मिनट में एक महिला इस बीमारी से जान गंवाती है।

कैंसर का मुख्य कारण- इस कैंसर के 95: से अधिक मामलों का कारण केवल एक वायरस है HPV (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) है।

जनगणना की तैयारी पूरी : जिले में 1 मई से शुरू होगा मकान सूचीकरण अभियान

बीजापुर। जिले में आगामी जनगणना कार्य को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके तहत जनगणना से जुड़े कर्मचारियों की तीन दिवसीय सघन प्रशिक्षण प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस अभियान में जिले के कुल 594 प्रगणक और 105 सुपरवाइजर भाग लेंगे, जिन्हें फील्ड ट्रेनरों के माध्यम से विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनगणना का प्रथम चरण 1 मई से 30 मई तक संचालित किया जाएगा जिसमें मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर आवश्यक सांख्यिकीय जानकारी एकत्र करेंगे। जिले के प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं कलेक्टर संबित मिश्रा ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से सतर्क रहें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान केवल सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत जानकारी। साथ ही, नागरिकों को यह भी जानकारी दी गई है कि जनगणना के दौरान किसी भी प्रकार की संवेदनशील जानकारी जैसे ओटीपी, बैंक खाता नंबर, पैन कार्ड या आधार नंबर नहीं मांगा जाएगा। यदि कोई ऐसी जानकारी मांगता है। तो तुरंत सतर्क हो जाएं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सही और सटीक जानकारी प्रदान कर सरकार के नीति निर्माण में सहभागी बनें।

तेंदूपत्ता खरीदी बंद होने से बढ़ी आदिवासियों की परेशानी, पुनः शुरू कराने की मांग, दिया ज्ञापन

सुकमा। जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण के बीच अचानक खरीदी बंद किए जाने से आदिवासी संग्राहकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस संबंध में बस्तरिया राज मोर्चा जिला समिति सुकमा ने वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर तत्काल पूर्ण खरीदी शुरू कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि जिले के कई समितियों में तेंदूपत्ता खरीदी केवल 1 से 3 दिनों तक ही की गई और उसके बाद फड़ बंद कर दिए गए। इससे संग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी मात्रा में तेंदूपत्ता अब भी तोड़ाई शेष है। अचानक खरीदी बंद होने से आदिवासी परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई समितियों में अब तक फड़ शुरू ही नहीं किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों में असंतोष है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक सीमित मात्रा में ही मानक बोरा खरीदा गया है, जबकि लक्ष्य अभी अधूरा है। ऐसे में खरीदी बंद करना समझ से परे है। समिति ने अपनी मांगों में कहा है कि जिले की सभी समितियों में तेंदूपत्ता का पूरा-पूरा खरीदी किया जाए, जिन क्षेत्रों में फड़ बंद कर दिए गए हैं उन्हें तत्काल पुनः चालू किया जाए, तथा खरीदी अवधि को कम से कम एक सप्ताह तक बढ़ाया जाए। साथ ही जब तक पूरी खरीदी नहीं हो जाती, तब तक फड़ बंद न करने की मांग की गई है। समिति का कहना है कि तेंदूपत्ता आदिवासी समुदाय की आय का मुख्य स्रोत है, इसलिए शासन-प्रशासन को इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।

संक्षिप्त समाचार

जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की बैठक संपन्न, 58.55 करोड़ के निवेश से 18 नए उद्योग स्थापित

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की बैठक आज कलेक्टर परिसर स्थित मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिले में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा निवेश संबंधी प्रकरणों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में नवीन उद्योग स्थापना, शासकीय एवं निजी भूमि के संयुक्त स्थल निरीक्षण, भूमि हस्तांतरण एवं अधिग्रहण, उद्योग स्थापना में आने वाली समस्याओं के निराकरण, औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा निजी सीबीएसई विद्यालय एवं मिनी मॉल की स्थापना हेतु संभावित नगरीय निकायों/विकासखंडों के संबंध में चर्चा की गई।जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक श्री सी.डी. प्रसाद द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में कुल 18 उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनमें 58.55 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इन उद्योगों के माध्यम से 278 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुभाग एवं तहसील स्तर पर लंबित शासकीय भूमि हस्तांतरण एवं निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए। साथ ही उद्योग स्थापना से संबंधित विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भूमि डायवर्सन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।बैठक में हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत 17 के लक्ष्य के विरुद्ध 61 प्रकरण स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 23 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) अंतर्गत 110 के लक्ष्य के विरुद्ध 111 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 89 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। पूर्व बैठक के निर्देशों के पालन में औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी ओव्हरब्रिज में प्रकाश व्यवस्था सुधार के संबंध में जानकारी दी गई कि 120 वाट हाईमास्ट लाइट स्थापना हेतु 10 अप्रैल 2026 को निविदा प्रकाशित की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 5 मई 2026 निर्धारित है। कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्र में बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित होगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अंबिकापुर में तालाब घोटाले का बड़ा खुलासाः 6.25 एकड़ घटकर 57 डिसमिल

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित रिंग रोड बांध तालाब मामले में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिंग रोड बांध सहित कई तालाबों पर अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए नामांतरण किए जाने के आरोप सामने आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मिश्रा ने दावा किया है कि लगभग 6.25 एकड़ क्षेत्रफल वाला तालाब अब सिमटकर मात्र 57 डिसमिल रह गया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि जनवरी 2026 में बची हुई जमीन की भी रजिस्ट्री कर दी गई। मामले में यह भी कहा जा रहा है कि तालाब क्षेत्र को रातों-रात पाटकर कब्जा किया गया और फर्जी कागजात के आधार पर जमीन का नामांतरण कराया गया। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जयलाल नामक व्यक्ति के दो अलग-अलग मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आए हैं। एक प्रमाण पत्र में मृत्यु तिथि 23 अप्रैल 1976 (जारी वर्ष 2018) दर्ज है, जबकि दूसरे में 12 अप्रैल 1963 (जारी वर्ष 2025) बताई गई है। इससे दस्तावेजों की सत्यता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा, पटवारी और तहसील स्तर पर अनियमितताओं, वंशवृक्ष में गड़बड़ी, बिना तारीख के आधिकारिक पत्र जारी होने और अलग-अलग मामलों में अलग-अलग वंशवृक्ष प्रस्तुत किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं।

बलरामपुर में 22 हाथियों का दल सक्रिय

बलरामपुर। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में हाथियों का बड़ा दल पिछले एक माह से लगातार सक्रिय है। जानकारी के अनुसार, करीब 22 हाथियों का झुंड रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है, जिससे आसपास के गांवों में भय का माहौल बना हुआ है। यह दल शिवपुर, फुलवार, लोधा और महावीरगंज सहित कई इलाकों में लगातार घूम रहा है। कई बार हाथियों का समूह मुख्य सड़कों तक पहुंच गया, जिससे राहगीरों में दहशत फैल गई और आवाजाही प्रभावित हुई। वन विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है

30 अप्रैल तक लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश

सुशासन तिहार और जनगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार

- 1 मई से दो बड़े अभियान शुरू : 73 शिविरों के साथ सुशासन तिहार
- टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल की समीक्षा, प्रशासनिक तैयारियों को दिया अंतिम रूप

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक लेकर आगामी 1 मई से शुरू हो रहे सुशासन तिहार और जनगणना कार्य की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 30 अप्रैल तक सभी लंबित मामलों के निराकरण के निर्देश देते हुए दोनों महत्वपूर्ण अभियानों को सफल बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य करने को कहा।कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित टीएल बैठक में जिले में शुरू होने जा रहे दो बड़े अभियानोंक सुशासन तिहार और जनगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुशासन तिहार प्रारंभ होने से पहले सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण कर लिया जाए, ताकि शिविरों में आमजन को त्वरित राहत मिल सके। कलेक्टर ने बताया कि जिले में सुशासन तिहार के दौरान कुल 73 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 31 शिविर ग्रामीण क्षेत्रों और 42 शिविर शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के संचालन की जिम्मेदारी जनपद पंचायत के सीईओ तथा शहरी क्षेत्रों में निगम आयुक्त एवं संबंधित सीएमओ को सौंपी गई है। शिविर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित स्थलों पर आयोजित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को समय पर उपस्थित रहने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर शिविरों की जानकारी देने के निर्देश दिए।बैठक में 1 मई से शुरू हो रही जनगणना की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने

नागरिकों से 30 अप्रैल तक स्व-गणना फॉर्म भरने की अपील करते हुए कहा कि जनगणना में जानकारी देना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। जानकारी न देने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना से प्राप्त जानकारी का उपयोग केवल नीति निर्माण के लिए किया जाएगा तथा जनगणना अधिनियम 1948 के तहत डेटा की गोपनीयता पूर्णतः सुरक्षित रखी जाएगी। 1 मई से प्रगणक घर-घर जाकर 34 बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित करेंगे। कलेक्टर ने जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया, जिनसे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और जिनके लिए अन्य स्रोतों से पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शेष पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में 1.02 लाख किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि लगभग 25 हजार और किसानों को इससे जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद और बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अग्रिस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों को ही खाद उपलब्ध कराया जाएगा और 1 मई से सॉफ्टवेयर शुरू होने पर वितरण प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बैठक में आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने टीएल, जनदर्शन, मुख्यमंत्री घोषणाओं, पीएम पोर्टल तथा उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

दलहन तिलहन की भी सरकार समर्थन मूल्य पर कर रही खरीदी

बिलासपुर। जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के अंतर्गत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है। इस पहल से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो रहा है और बाजार के उतार-चढ़ाव से राहत मिल रही है। जिले में बिल्हा, सेंदरी, जयरामनगर, तखतपुर और कोटा स्थित 5 सोसाइटी के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों पर चना 5875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 7000 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों 6500 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य तय किया गया है। अब तक जिले में कुल 548 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिससे योजना के प्रति किसानों की बढ़ती रुचि स्पष्ट हो रही है। खरीदी कार्य भी धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। वर्तमान में 5

किसानों से 26 क्विंटल चना तथा 8 किसानों से 90 क्विंटल सरसों की खरीदी की जा चुकी है। प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर अपनी उपज का विक्रय करें और शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं। सरसों फसल के लिए 30 अप्रैल एवं चना फसल के लिए 15 मई तक किसान समिति के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते है।

जनदर्शन में मेधू राम को मिली त्वरित राहत, कलेक्टर ने सौंपी व्हीलचेयर.....

बिलासपुर। जनदर्शन कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता और तत्परता से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आयोजित जनदर्शन में दिव्यांग वृद्ध श्री मेधूराम खांडे की समस्या का तत्काल समाधान करते हुए मौके पर ही कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल द्वारा श्री खांडे को व्हीलचेयर प्रदान की गई।जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में इमलीभाटा अंबेडकर आवास, सरकंडा निवासी श्री मेधू राम खांडे को त्वरित लाभ मिला। वे अपनी समस्या लेकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए व्हीलचेयर की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए

आवेदन पर तत्काल संज्ञान लिया और बिना किसी देरी के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही श्री मेधू राम खांडे को व्हीलचेयर प्रदान किया गया। इस दौरान एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक श्री टीपी भावे भी मौजूद थे। इस सहायता से लाभार्थी मेधू राम खांडे के चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव देखे गए।

पत्नी से नाराज युवक 400 फीट ऊंचे हाईटेंशन टावर पर चढ़ा.....

मरवाही। जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत जिल्दा गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक 33 केवी हाईटेंशन लाइन के करीब 400 फिट ऊंचे टावर पर चढ़कर ऊपर जा बैठा। युवक को इतनी ऊंचाई पर देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार, 25 वर्षीय केवल सिंह आयाम अपनी पत्नी से नाराज था। उसकी पत्नी बीते 3-4 दिनों से गांव में अपने रिश्तेदार के यहां आयोजित विवाह कार्यक्रम में गई हुई थी और वापस नहीं लौटी थी। इसी बात से आक्रोशित होकर युवक ने यह खतरनाक कदम उठा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक टावर के शीर्ष पर पहुंचकर करीब 2 से 3 घंटे तक वहीं बैठा रहा। इस दौरान नीचे खड़े परिजन और ग्रामीण उसे लगातार समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वह नीचे आने को तैयार नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। संभावित खतरे को देखते हुए तत्काल बिजली विभाग से संपर्क कर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कराई गई। इसके बाद संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। लंबी समझाइश और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ मौजूद रही और सभी की नजरें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी रहीं। पुलिस ने बताया कि युवक पूरी तरह सुरक्षित है और उससे पूछताछ की जा रही है।

सुशासन तिहार में पानी पर फोकस :749 हैंडपंप सुधार,154 गांव में रिचार्ज प्लान

- ग्रामीण पेयजल व्यवस्था मजबूत करने विशेष अभियान, हजारों मीटर पाइपलाइन बढ़ाई गई

बिलासपुर। सुशासन तिहार एवं चालू गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला प्रशासन के सहयोग से जिले में विशेष संधारण अभियान चलाकर पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में पिछले एक माह के दौरान चलाए गए इस अभियान के तहत खराब पड़े 749 हैंडपंपों का सफलतापूर्वक सुधार किया गया।

इससे ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। अभियान के दौरान जल उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 1335 मीटर राइजर पाइप बढ़ाए गए तथा 732 मीटर पाइपों का प्रतिस्थापन किया गया है। वर्तमान में जिले के 668 ग्रामों में कुल 9250 हैंडपंप स्थापित हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल परिरक्षण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही, पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले बोरिंग कार्यों में तकनीकी स्वीकृति के दौरान इंजेक्शन वेल को अनिवार्य किया गया है, जिससे भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिल सके। भूजल संवर्धन के तहत जिले के सभी चारों विकासखंडों में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 154 ग्रामों में इंजेक्शन वेल सहित स्रोत स्थिरता के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जो दीर्घकालीन जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। जिला प्रशासन द्वारा पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं भूजल स्तर के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आमजन को गर्मी के मौसम में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े।

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

बिलासपुर। जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आज कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने कलेक्टर से मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। कलेक्टर ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल एवं संयुक्त कलेक्टर श्री एसएस दुबे ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में आज ग्राम भुरकुण्डा के ग्रामीणों ने बड़े नहर पार मार्ग पर वर्षों से सड़क नहीं बनने की समस्या उठाई। उनका कहना है कि खुटाघाट से सोन तक करीब 46-47 मील के बीच चार पहिया वाहन नहीं चल पाते और बरसात के समय पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क निर्माण कराने की मांग की है। वहीं एक अन्य आवेदन में ग्राम रांक के निवासी नवल किशोरे ने मिशल, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रशासन से जल्द प्रमाण पत्र जारी करने की अपील की। ग्राम रांक से ही इंदल बंजारे द्वारा पेयजल और बिजली से संबंधित समस्या रखी गई। ग्रामीण ने बताया कि पूर्व में बने बोर को बंद कर दिए जाने से पानी की समस्या बढ़ गई है, वहीं लगातार बिजली कटौती से हालात और खराब हो रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से पानी और बिजली की व्यवस्था सुधारने की मांग की। भुरकुण्डा के ग्रामीणों ने भुरकुण्डा और सोढाडीह के बीच छोटे नाले पर पुलिया (रपटा) निर्माण के संबंध में

कलेक्टर से मुलाकात की। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया नहीं होने से आवागमन बाधित होता है, खासकर बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। ग्राम चोरा के ग्रामीणों न कलेक्टर के समक्ष गंगा मछवारा समिति के विरूद्ध शिकायत करते हुए कहा कि तालाब का पानी मछली पालन के लिए पूरी तरह उपयोग कर लिया जाता है, जिससे हैंडपंप और कुओं का जलस्तर गिर गया है और पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है। ग्रामीणों ने उचित कार्रवाई कर तालाब के उपयोग को संतुलित करने की मांग की है। मस्तुरी के एरमसाही निवासी सियाराम कुर्रे ने भूमि सीमांकन न होने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि सीमांकन नहीं होने के कारण भूमि संबंधी कार्य अटके हुए हैं और उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र सीमांकन कराने की मांग की है। बिल्हा तहसील के ग्राम कुंआ बोड़सरा के ग्रामीणों ने बोड़सरा धाम के मेला परिसर में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने बताया कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन पानी की उचित व्यवस्था न होने से विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

पानी पाउच बहाना बनाकर बाइक चोरी,7 दिन में चोर गिरफ्तार

बिलासपुर। मस्तूरी क्षेत्र की चौकी मल्हार पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को महज 7 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है, जहां आरोपी ने बेहद चालाकी से लिफ्ट मांगकर वारदात को अंजाम दिया था। मामला 20 अप्रैल 2026 का है, जब प्रार्थी भारत लाल केवट, निवासी ग्राम पकरिया थाना मुलमुला जिला जांजगीर-चांपा, अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक इत 11 क्रा 4552 से ससुराल वेदपरसदा मस्तूरी आया हुआ था, वापसी के दौरान रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने लिफ्ट मांगी और बुढ़िखार गांव पहुंचते ही उसने पानी पाउच लाने का बहाना बनाकर प्रार्थी को होटल भेज दिया, जैसे ही प्रार्थी दुकान की ओर गया, आरोपी मौके का फायदा उठाकर बाइक लेकर फरार हो गया और कुछ ही पलों में गायब हो गया। पीड़ित ने आसपास काफी तलाश की लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो चौकी मल्हार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच शुरू की, फुटेज खंगाले गए, संदिग्ध की तस्वीर निकाली गई और अलग-अलग गांवों में लोगों को दिखाकर पहचान की कोशिश की गई, इसी दौरान मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि ग्राम गीधपुरी निवासी नरोत्तम दास वैष्णव (उम्र 55 वर्ष) ने चोरी की बाइक को अपने घर में कपड़े से ढंककर छुपा रखा है।

गर्मियों में हेल्दी रहने के लिए रामबाण है नारियल पानी

वजन घटाएं, स्किन में भी लाए निखार

गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। इन दिनों में जब लोग घर से निकलते हैं तो भीषण गर्मी के कारण गला सूखने लगता है। कई बार लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इसलिए गर्मियों में अपने शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है। यही वजह है कि इस मौसम में फलों, हरी सब्जियों और जूस का सेवन करने की सलाह एक्सपर्ट भी देते हैं। गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है। यह शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है।

दिल को रखे सेहतमंद: मेडिकलन्यूजटुडे के मुताबिक, दिल के मरीजों के लिए, नारियल पानी बहुत फायदेमंद होता है। नारियल पानी में भरपूर मात्रा में पोटैशियम पाया जाता है। ये पोटैशियम हाई ब्लड प्रेशर और दिल के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है।

त्वचा में लाए निखार: नारियल पानी पीने से हमारे शरीर के साथ स्किन भी हाइड्रेट रहती है, जिससे त्वचा संबंधी कई परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। नारियल पानी पीने से त्वचा में निखार तो आता ही है, साथ ही पिंपल्स और रैशेज की समस्याएं भी दूर होती है।

हड्डियों की मजबूती: नारियल पानी हड्डी से जुड़ी कई प्रकार की बीमारियों में फायदा पहुंचाता है। नारियल पानी में कैल्शियम मौजूद होता है, जो दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने में काफी असरदार होता है।

वजन कम करता है: नारियल पानी में फैट की मात्रा बहुत कम होती है। यह पूरे दिन आपको तरोताजा महसूस कराता है। यही वजह है कि मोटापे से ग्रसित लोगों को नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है।

शरीर को रखे हाइड्रेटेड: नारियल पानी में 95 फीसदी पानी ही होता है, इसलिए इसे पीते रहने पर शरीर में पानी की कमी नहीं होने पाती। साथ ही यह कई तरह के पोषक-तत्वों से भरपूर और शुगर-फ्री भी होता है।

जिम करना

गर्मियों में पड़ सकता है महंगा

स्वस्थ शरीर के लिए रोजाना एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। यही वजह है कि कई लोग फिट रहने के लिए रोजाना जिम करते हैं। गर्मी हो या सर्दी कुछ लोग वजन कम करने के लिए घंटों जिम में बिताते हैं। लेकिन गर्मियों में वर्कआउट करते समय ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। धीरे-धीरे तापमान बढ़ता जाएगा। ऐसे में वर्कआउट के सही समय और इसको लेकर बरते जाने वाली सावधानियों को जानना बेहद जरूरी है। सर्दी का मौसम एक्सरसाइज के लिए बेस्ट होता है, लेकिन अब लोग सेहत के प्रति इतने अलर्ट हो गए हैं कि गर्मी में भी घंटों वर्कआउट करते हैं। इस मौसम में तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यह अधिक एक्सरसाइज के लिए सही मौसम नहीं होता। अगर किसी को पहली बार जिम शुरू करनी है तो बेहतर होगा कि वो सर्दी के मौसम से शुरू करें।

गर्मी में कब करें एक्सरसाइज?
मौसम गर्मी का हो या फिर सर्दी का एक्सरसाइज करने का सबसे बेहतर समय सुबह का होता है। अगर गर्मी अधिक है, तो एक्सरसाइज करने से पहले ठंडे पानी से स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद एक्सरसाइज या वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट के बाद जब शरीर थोड़ा कूल हो जाए, तो नाश्ता करके फिर से नहा लें। इससे शरीर को आराम महसूस होगा।
गर्मियों में अगर एक्सरसाइज एसी वाली जगह पर कर रहे हैं, तो ये बेस्ट है। एक्सरसाइज करने से पसीना अधिक होता है, ऐसे में पानी का सेवन खूब करना चाहिए। गर्मी के मौसम में कार्डियो एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग ज्यादा करना चाहिए। जिन लोगों को कोई समस्या जैसे हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, फेफड़े की समस्या है, तो उन्हें हेवी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। इसकी बजाय टहल सकते हैं या फिर जॉगिंग कर सकते हैं।

चाहते हैं बुढ़ापे में हड्डियां बनी रहें मजबूत

अभी से ही इन फूड्स से बना लें दूरी

इन फूड से करें परहेज

1. नमकीन चीजों से परहेज- बोन हेल्थ एंड ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने अपने अध्ययन में पाया है कि ज्यादा नमकीन वाले फूड बोन हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। इससे हड्डियों से कैल्शियम का क्षय होने लगता है। अध्ययन के मुताबिक ब्रेड रोल, पिज्जा, सैंडविच, सूप, चिप्स, पॉपकॉर्न, स्नैक्स मिक्स, क्रेकर्स, चिकन, चीज, एग और ऑमलेट में ज्यादा नमक होता है। ज्यादा सेवन करने से हड्डियों से कैल्शियम गायब हो सकता है।
2. अल्कोहल-शराब का सेवन वैसे तो किसी मायने में बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थराइटिस एंड मस्कुलोस्केलटल ने अपने अध्ययन में बताया है कि अल्कोहल शरीर को विटामिन डी और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विलेन का काम करता है।
3. ज्यादा मीठा-पबमेड सेंट्रल के अध्ययन में पाया गया कि ज्यादा चीनी वाली चीजों के सेवन से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम रिसकर पेशाब के रास्ते बाहर हो जाता है। वहीं यह कैल्शियम के एब्जोर्बान में दिक्कत पेश करता है। कैंडी, पेस्ट्री, केक, प्रोसेस्ड फूड, सॉस, डिजर्ट स्वीट्स आदि में ज्यादा चीनी होती है।
4. हाई ऑक्सीलेट-कुछ फूड में ऑक्सीलेट और फायटेट्स कंपाउंड ज्यादा होते हैं। ये फूड कैल्शियम के एब्जॉर्बान को धीमा कर देते हैं। इसलिए ऐसे फूड के सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये फूड हैं पालक और अन्य हरी पत्तीदार सब्जियां, बीन्स और चाय। इन चीजों का कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। ज्यादा से नुकसान हो सकता है।

कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कैल्शियम के नुकसान को बढ़ाता है, यही कारण है कि कुछ लोगों को बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। यह बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। इसमें उठना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि किन फूड का ज्यादा सेवन करने से हड्डियां बुढ़ापे में दगा दे देंगी। हड्डियों की मजबूती बरकरार रखने के लिए कैल्शियम के अलावा विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, प्रोटीन और कई अन्य तरह के मिनिरल्स की जरूरत होती है। इन सबको शरीर में सही से ए जोर्ब करने में कुछ फूड का ज्यादा सेवन नुकसान पहुंचाता है।

पालक का जूस ही नहीं, पानी भी बेहद लाभकारी

लाइफ एंड ट्रेंड्स वेबसाइट के अनुसार, पोषक तत्वों से भरपूर हरी सब्जियां सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। हरी पत्तेदार पालक की सब्जी आपके शरीर को विटामिन, मिनिरल और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करती है, इसलिए आपको इसे अपने आहार में शामिल करने के साथ ही इसको जूस के रूप में जरूर लेना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर पालक की बाजारों में सबसे अधिक मांग होती है। आप ताजा पालक को मिक्सर में डाल कर पानी के साथ पीस कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इसको पकाकर खाने की सलाह देते हैं, लेकिन यदि आप इसका जूस निकाल कर पीएंगे तो सेहत के लिए अच्छा होगा। कई बार लोग पालक पनीर, पालक पराठा या सब्जी बनाने के लिए इसके पत्तों को उबालते हैं तो, इसके पानी को फेंक देते हैं। जबकि, इस पानी में सबसे ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। इस पानी का सेवन करेंगे तो कई शारीरिक बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं इसका सेवन करने से होने वाले लाभ-

पेट के लिए फायदेमंद है
पालक का पानी पेट के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है। पालक के पोषक तत्वों में आहार फाइबर भी शामिल है। ये आपका मेटाबोलिज्म बढ़ाता है और पेट के काम काज को तेज करता है। इससे कब्ज की समस्या नहीं होती है।

आंखों की रोशनी बढ़ाता है पालक का पानी
पालक के पानी में ल्यूटिन और जेक्साथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। साथ ही इसमें इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाए, तो यह सूखी आंखें और रतौंधी का कारण बन सकता है।

स्वास्थ्य के साथ निखारता है रूप

बालों के लिए फायदेमंद पालक का पानी
पालक के पानी का सेवन सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है। इसमें कई प्रकार के न्यूट्रीएंट्स जैसे आयरन और प्रोटीन होता है जो कि बालों को अंदर से मजबूत और खूबसूरत बनाने में मदद करता है।

स्किन हेल्दी रखता है पालक का पानी
पालक का पानी पीना आंखों और बालों के साथ ही स्किन को भी हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। पालक का पानी शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है। इससे चलते शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और स्किन अंदर से ग्लो करती है।'

इम्यूनिटी बढ़ाता है पालक का पानी
पालक में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसलिए पालक का पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और पुरानी बीमारियों खत्म होती हैं।

कैंसर को रोकता है पालक का पानी
पालक जहां दिल से संबंधित बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है, वहीं यह कैंसर को भी नष्ट करने में मदद कर सकता है। शोध बताते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से वजन कम हो सकता है, साथ ही फेफड़े, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर की संभावना भी खत्म हो सकती है।

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है
पालक के पानी में स्वाभाविक रूप से नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक होती है। इसलिए यह रक्तचाप को कम करने में मदद करता है और रक्तचाप को बढ़ाता है।

दही में नमक डालकर खाना फायदेमंद या गुड़-चीनी?

गर्मियों का मौसम आने वाला है और लोगों को इस मौसम में दही खूब भाता है। कुछ लोग दही में चीनी मिलाकर खाते हैं, तो कुछ लोग नमक के साथ इसका लुत्फ उठाते हैं। तमाम लोग दही की लस्सी बनाकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते हैं। आपने भी कई तरीकों से दही का सेवन किया होगा। अब सवाल उठता है कि दही में नमक डालकर खाने से शरीर को ज्यादा फायदा मिलता है या गुड़ और शक्कर मिलाकर खाना ज्यादा लाभकारी है। इस बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टर से हकीकत जान लेते हैं।

भले ही दही को गर्मी से राहत पाने के लिए खाया जाता है, लेकिन दही की तासीर गर्म होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और इसे बिना कुछ मिलाए नहीं खाना चाहिए। सादा दही हमारे खून को दूषित कर सकता है और स्किन की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आयुर्वेद में साफ कहा गया है कि दही को रात के वक्त खाने से बचना चाहिए और इसका रोज सेवन नहीं करना चाहिए। दही में मूंग की डाल, शहद, घी, शक्कर और आंवला को मिलाकर खाने से हेल्थ को कई बड़े फायदे मिलते हैं।

दही में नमक मिलाकर चाहिए या चीनी?
दही में कभी कभार नमक मिलाकर खा सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। दही की तासीर गर्म होती है और उसमें ज्यादा नमक मिलाकर खाने से स्किन की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसा करने से हेयर फॉल, उम्र से पहले सफेद बाल और स्किन पर फुंसी हो सकती हैं। इसलिए दही में नमक डालने से बचना चाहिए। चीनी की बात करें तो दही में चीनी मिलाकर खाना बेहद फायदेमंद माना जाता है। दही में जब चीनी मिला दी जाती है तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता। दही में गुड़ मिलाना भी बेहद लाभकारी है। आयुर्वेदिक डॉक्टर की मानें तो दही की लस्सी बनाकर पीना गर्मियों में लाभकारी होता है। जब दही में चीनी मिल जाती है तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और इसका सेवन से गर्मी से राहत मिलती है।

डार्क अंडरआर्म्स को इन घरेलू उपायों से करें दूर

स्लीवलेस ड्रेस में नहीं होगी परेशानी

गर्मी के मौसम में बिना बाजू वाले ड्रेस पहनना लोग काफी पसंद करते हैं। ये कंफर्टेबल होते हैं और गर्मी में दिखते भी अच्छे हैं। लेकिन कई लोगों की समस्या होती है कि ऐसे कपड़े पहनने से उनके अंडर आर्म का कालापन नजर आता है और सभी की नजरें उनके डार्क अंडरआर्म पर अटती है। अगर आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं तो यहां हम आपके साथ कुछ ऐसे घरेलू उपाय शेयर कर रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने अंडर आर्म की स्किन को ब्राइट और क्लीन बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

नींबू का इस्तेमाल-
नींबू की मदद से आप अपने काले अंडरआर्म के दाग को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप आधा नींबू काट लें और यहां की स्किन पर लगा लें। आधे घंटे के बाद नहा लें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप पैच टेस्ट के बाद ही इसका इस्तेमाल करें।

एप्पल साइडर विनेगर-
एप्पल साइडर विनेगर में भी माइल्ड ब्लीच के गुण हैं जो नेचुरल क्लीनर की तरह भी काम कर सकता है। आप इसकी मदद से स्किन के कालेपन को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कॉटन को एप्पल साइडर विनेगर में डुबाएं और से स्किन पर लगाएं। ऐसा रोज करने पर दाग चले जाएंगे।

नारियल तेल-
नारियल तेल स्किन के लिए कई तरह से फायदेमंद है। यह स्किन को नरिश तो करता ही है, डार्क स्किन की समस्या को भी दूर कर सकता है। आप रोज रात में अंडरआर्म की स्किन पर नारियल तेल लगाएं और रातभर छोड़ दें। स्किन पर निखार आएगा।

बेकिंग सोडा-
बेकिंग सोडा की मदद से आप स्किन को ब्राइट और क्लीन बना सकते हैं। इसके लिए सप्ताह में एक या दो दिन बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को त्वचा पर लगाएं। 15 मिनट के बाद स्किन से इसे अच्छी तरह से धो लें।

एलोवेरा-
आप ताजा एलोवेरा के पत्तों से जेल निकालें और इसे अंडर आर्म की स्किन पर लगाएं। आप नहाने के बाद या सोने से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे स्किन के रंगत में अंतर नजर आने लगेगा।

रिश्ते में प्यार के साथ मिलेगा सम्मान

ऐसे जीते पार्टनर का दिल

हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें। खासतौर पर पार्टनर के साथ संबंध कितना मजबूत है, यह भी आपस में एक-दूसरे के व्यवहार और सम्मान को देखकर पता चलता है। दरअसल, जब आप अपनी चीजों की इज्जत करते हैं या खुद की इज्जत करते हैं तो आप लोगों के सामने इस बर्ताव के मॉडल बनते हैं। यह आपके इज्जत को बढ़ाने का एक जरिया हो जाता है। इसमें वे सारी बातें शामिल होती हैं जो किसी का भी अटेंशन आपकी तरफ खींचता है। मसलन, आप कितने अच्छे श्रोता हैं और आप कितनी रुचि से उनकी बातों को सुनते हैं। ये सारी बातें आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करती है। यहां हम आपको बताते हैं कि आप रिश्ते में किस तरह एक-दूसरे से सम्मान हासिल कर सकते हैं।

शक्ति नहीं, स्नेह दें
अगर आप बात बात पर अपने पावर को प्रदर्शित कर रहे हैं तो बता दें कि आप ऐसा करने से अपना सम्मान खो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते में पावर से अधिक स्नेह दर्शाते हैं और आप अपने पार्टनर की जरूरतों को जानने और पूरा करने का प्रयास करते हैं, बात बात पर पार्टनर की सराहना करते हैं, तो इससे आपके प्रति प्यार और इज्जत अपने आप बढ़ने लगती है।

बिहेवियर में बनाएं बैलेंस
अगर आप अपने पार्टनर को खूब प्यार करते हैं लेकिन उनके साथ कभी कभी बहुत अधिक बुरा व्यवहार भी कर देते हैं तो इससे आपका रिलेशनशिप बर्बाद हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बिहेवियर में बैलेंस बनाएं। आप अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से बोलना सीखें और इच्छाओं को भी बताएं। लेकिन सही बर्ताव के साथ। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी।

सीमा करें निर्धारित
जब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनर के बीच भागीदारी और सीमाएं जरूरी होती हैं। इसी तरह रिलेशनशिप को भी बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ सीमाएं बनाएं। मसलन, अगर आपका पार्टनर शॉपिंग पर साथ जाना चाहता है लेकिन आप दिनभर ऑफिस में वक्त गुजार रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप आपस में बात करें और बीच का उपाय निकालें।

सेल्फ रिस्पेक्ट करें
जब आप खुद की इज्जत करते हैं तो जमाना भी आपकी इज्जत करता है। यह नियम रिलेशनशिप में भी लागू होता है। जब आप अपनी जरूरतों, इच्छाओं, अपनी चीजों को सम्हालकर रखते हैं या उनका केयर करते हैं तो आपकी इज्जत बढ़ती है और पार्टनर से भी आपको इज्जत मिलने लगती है। मसलन, आप अपने परिवार का वैल्यू करते हैं, अपने रिश्ते की परवाह करते हैं आदि।

खुद की जरूरतों को समझें
अपनी जरूरतों को समझना जरूरी है। इस बात को समझें कि कहीं आपकी जरूरतें रिश्तों पर हावी तो नहीं हो रही। रिश्ते में सम्मान पाने के लिए जरूरी है कि आप खुद के साथ साथ अपने पार्टनर की जरूरतों को भी जानें और दोनों के बीच तालमेल बिठाएं।

राज्यपाल रमेन डेका ने ली ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक

जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने पर दिया जोर

जैविक खेती व हाइड्रोपोनिक्स खेती को बढ़ावा देने की बात कही

स्कूलों में शौचालय की सुविधा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में जिले के ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान राज्यपाल श्री डेका ने लोक निर्माण विभाग के प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि अधिकारी हितग्राहियों से व्यक्तिगत रूप से मिलें और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का फीडबैक लें। सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

बैठक के दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों का आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्री-मानसून (मानसून शुरू होने से पहले) और पोस्ट-मानसून (मानसून समाप्त होने के बाद) दोनों अवधियों में भूजल स्तर का नियमित और व्यवस्थित मापन किया जाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों समयावधियों के आंकड़ों की तुलना करने से यह स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि वर्षा के साथ-साथ जिले में चलाए गए जल संवर्धन अभियानों जैसे सोखपीट निर्माण और अन्य संरचनाओं का भूजल स्तर पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाया जाता है, तो न केवल जल स्तर में हो रही वास्तविक वृद्धि का सही आंकलन संभव होगा, बल्कि जल संरक्षण के प्रयासों को और बेहतर दिशा भी दी जा सकेगी।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, शासकीय भवनों, सड़कों के किनारे तथा सिविल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराने को कहा, ताकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। राज्यपाल ने ÷एक पेड़ मां के नाम÷ अभियान को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से आम लोगों की सहभागिता बढ़ेगी और वे वृक्षारोपण के प्रति अधिक जागरूक एवं प्रेरित होंगे। राज्यपाल ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में धान की खेती अधिक मात्रा में होती है, जिससे पानी की खपत भी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को अन्य कम पानी वाली फसलों की ओर भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही राज्यपाल ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर बल देते हुए हाइड्रोपोनिक्स खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स एक उन्नत तकनीक है, जिसमें फसलों को बिना मिट्टी के केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल के माध्यम से उगाया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बेहतर मिलता है। बैठक में कृषि अधिकारी ने जानकारी दी कि ÷नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग÷ के तहत जिले में 500 किसानों को जैविक खेती से जोड़ा गया है और वे जैविक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।

राज्यपाल श्री डेका ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों में शौचालय की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक स्कूल में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा वे साफ-सुथरे और उपयोग योग्य स्थिति में हों। उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों के शौचालयों का निरीक्षण करने के लिए कहा। राज्यपाल ने यह भी जोर दिया कि शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही राज्यपाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि ड्रॉपआउट हुए बच्चों और उनके अभिभावकों की बैठकें आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और वर्तमान में किसी अच्छे संस्थान में कार्य कर रहे हैं या किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, उन्हें स्कूलों में आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए। ऐसे कार्यक्रमों से वर्तमान विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी और वे भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित योग और व्यायाम को बढ़ावा देने पर राज्यपाल ने जोर दिया। जिले के 28 संस्थानों में नियमित रूप से योग का अभ्यास किया जा रहा है, जिसकी उन्होंने सराहना की। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन संस्थानों में नियमित योग करने वाले प्रतिभागियों की सूची तैयार कर भेजी जाए, ताकि उन्हें राजभवन में आमंत्रित कर सम्मानित किया जा सके।

राज्यपाल ने सभी विकासखंड अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जल संरक्षण के कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, स्कूलों में शौचालयों की स्थिति तथा ÷लखपति दीदी÷ योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में किए जा रहे किसी भी नवाचार (इनोवेटिव कार्य) की जानकारी भी ली, ताकि अच्छे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले की 92 प्रतिशत उपचार सफलता दर को सराहनीय बताया गया। ÷निक्षय मित्र पहल÷ के माध्यम से टीबी मरीजों को पोषण सहायता प्रदान करने के प्रयासों को और व्यापक बनाने के निर्देश दिए गए। जिले में 108 वृद्धजनों को मोतियाबिंद आपरेशन हेतु चिन्हांकित किया गया है जिसमें से 09 वृद्धजनों का आपरेशन किया जा चुका है शेष को आपरेशन हेतु एम्स रायपुर ले जाया जाएगा। जिले में विभागीय मान्यता व अनुदानित 02 वृद्धाश्रम संचालित है जिसमें वर्तमान में 86 वृद्धजन निवासरत है, जिसकी राज्यपाल श्री डेका ने सराहना की।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि स्थानीय उत्पादों के वेल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे उनकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य दोनों में वृद्धि हो सके। साथ ही इन उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। राज्यपाल ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर भी गंभीरता जताई और अधिकारियों को इसके लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। उन्होंने सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय लागू करने पर जोर दिया, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इसके साथ ही राज्यपाल ने इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने पर जोर दिया।

बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, अपर कलेक्टर विरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम पाटन लवकेश ध्रुव, एसडीएम भिलाई-3 महेश राजपूत, एसडीएम धमधा सोनल डेविड, एसडीएम उत्तम ध्रुव, नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा आयुक्त श दशरथ राजपूत, नगर निगम रिसाली आयुक्त मोनिका वर्मा, वनमण्डलाधिकारी दीपेश कपिल, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सनातन दसनाम गोस्वामी समाज का आयोजन

संत-महात्माओं के दिव्य सानिध्य में भगवान आध शंकराचार्य जयंती महोत्सव संपन्न

युवक युवती परिचय सम्मेलन सहित प्रतिभावान बच्चों का सम्मान

भिलाई। छत्तीसगढ़ सनातन दसनाम गोस्वामी समाज द्वारा 26 अप्रैल रविवार को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठाता शिवावतार भगवान आद्य शंकराचार्य जी का जयंती महोत्सव पूज्य संत-महात्माओं की दिव्य उपस्थिति एवं सानिध्य में समाज के महंतगण, संरक्षकगण और संस्थापक सदस्यों की उपस्थिति में गरिमामय कार्यक्रम संपन्न हुआ।

प्राकट्य उत्सव कार्यक्रम में अतिथि के रूप में दंडी स्वामी श्री ज्योतिर्मयानंद सरस्वती पीठाधीश्वर सपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा, महंत डॉ0 राम?सुंदर दास पीठाधीश्वर दूधाधारीमठ रायपुर,श्री श्री 1008 श्री विवेक गिरी महाराज थानापति गौरकांपा आश्रम लोरमी, महंत सच्चिदानंद गिरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गोस्वामी समाज नई दिल्ली एवं गौरकापा आश्रम के सन्यासी स्वामी शिवानंद महराज उपस्थित थे।कार्यक्रम में समाज के महंतगण हरभूषणगिरी कंकाली मठ रायपुर, सुरेन्द्रपुरी धमतरी (सोरर),विनोद पुरी मुंगेली, संरक्षक एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एल पी गोस्वामी, कोमल गिरी,चित्रसेन गिरी, प्रभाकर बन, प्रदेश अध्यक्ष मोहनपुरी गोस्वामी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पुरी गोस्वामी, प्रीतम गिरी,महासचिव संजय गिरी, कोषाध्यक्ष सुधीर बन की सहभागिता रही। गोस्वामी समाज के भागवत कथा व्यास दिनेश भारती पामगढ़ एवं युवा कवियित्री लेखिका डॉ0 शिखा गोस्वामी मारे की मंच पर प्रेरक प्रस्तुति उल्लेखनीय रही।प्रदेशाध्यक्ष मोहनपुरी के द्वारा स्वागत भाषण पश्चात अतिथियो द्वारा जगतगुरु आद्य शंकराचार्य भगवान द्वारा किए गए दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक कार्यो का स्मरण कर सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठ एवं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना के द्वारा सनातन हिन्दू-समाज में एकता, विश्वास, आस्था जागृत करने इत्यादि अतुल्य कार्यों हेतु उनके अमूल्य योगदान के लिए संपूर्ण सनातन धर्मालंबियों की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित कर उनके बताए उपदेशों का अनुशरण करते हुए अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को सार्थक करने का आव्हान किया गया। भगवान आद्य शंकराचार्यजी के द्वारा मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में किए गए दिव्य एवं अलौकिक कार्यों के कारण ही सनातन धर्म का वर्तमान स्वरूप विद्यमान एवं प्रभावी है। जिसके लिए भारतवर्ष के साथ संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबी आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठाता के रूप में संपूर्ण विश्व के मानव-समाज में उन्होंने आध्यात्मिक उर्जा एवं चेतना का संचार किया। जिसके लिए सनातन धर्म एवं अखिल विश्व का मानव समाज हमेशा ऋणी रहेगा। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ 10वी,12 वी में उत्कृष्ट परिणाम लाने वाले छात्र-छात्राओं, अलग अलग विधाओं में पारंगत समाज के लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर उत्साह वर्धन किया गया।कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रदेश महासचिव नरेन्द्र पुरी एवं आभार प्रदर्शन रायपुर जिलाध्यक्ष वेद पुरी द्वारा किया गया।इस अवसर पर दुर्ग अध्यक्ष दीपक बन, डा विजय गिरी, डॉ सुभाष पुरी, नंद पुरी,तिलक पुरी, लवकेश्वर पुरी, शंभु पुरी, सनत भारती,राजेंद्र भारती, विक्रांत बन, संतोष गिरी, नरेंद्र बन, खिलावन गिरी, भागवत गिरी, उमेश गिरी, चन्द्रशेखर भारती, राजेंद्र गिरी, सचिन गिरी,मयंक पुरी, प्रांजल पुरी,सौरभ गोस्वामी,प्रखर पुरी अक्षत बन,उदित गोस्वामी सहित महासमुंद, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, जगदलपुर, कांकेर, धमतरी,बेमेतरा, दुर्ग भिलाई, रायपुर से सैकड़ों की संख्या में सामाजिक लोगो की उपस्थिति रही।

दुर्ग जिले में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: चाट-गुपचुप से लेकर डेयरी और होटलों में सघन जांच, मैंगो जूस में रंग मिलाने की शिकायत

दुर्ग। सावधान अगर आप गर्मी के मौसम बाजार के ठेले खोमचे से अगर जूस पीते हैं तो क्योंकि इन दिनों जूस को गाढ़ा बनाने के लिए केमिकल वाले रंग के उपयोग किए जाने की शिकायतें सामने आ रही है। और इसी बढ़ती हुई शिकायतों को देखते हुए दुर्ग जिले के औषधि एवं खाद्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को पूरे जिले में व्यापक जांच अभियान चलाया। खाद्य विभाग की अलग-अलग टीमो ने शहर के प्रमुख चाट, गुपचुप सेंटर्स और गन्ना रस की दुकानों सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर दबिश दी।

इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई- जांच अभियान के दौरान टीम ने सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस सेंटर, आईसक्रीम पार्लर, डेयरी प्रोडक्ट विक्रेता, मिठाई दुकान, होटल और रेस्टोरेंट की बारीकी से जांच की। इसके साथ ही टीम केक एवं बेकरी यूनिट्स, मिड-डे-मील सेंटर्स, हॉस्पिटल कैंटीन और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट भी पहुंची। सड़कों के किनारे बिकने वाले आईस गोला, आईस कैंडी और पेप्सी विक्रेताओं के साथ-साथ फल व सब्जी दुकानों की भी सघन चेकिंग की गई।

निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर स्वच्छता और गुणवत्ता में भारी अनियमितता पाई गई, जिस पर टीम ने तत्काल आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा।

बता दें, टीम ने जब मौके पर निरीक्षण किया तो दुर्ग के पाण्डे जूस कार्नर, इंदिरा मार्केट, देवांगन जूस कार्नर, अग्रसेन चौक में मैंगो जूस में रंग मिलाया जा रहा था। रंग को मौके पर नष्ट कराया गया एवं भविष्य में रंग का प्रयोग करने, खराब एवं सड़े फलों का प्रयोग करने एवं नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की समझाइश दी गई।

अध्यक्ष बने मुकेश कुमार पाण्डेय उपाध्याक्ष विनोद कुमार पाण्डेय

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा संगठन के तत्वाधान में जनपद इकाई के पदाधिकारियो का चुनाव जिला पंचायत सभागार में मंगलवार के दिन किया गया। एसोसिएशन के कार्यकारिणी की बैठक के अध्यक्ष एवं महामंत्री पद पर आम सहमति न होने के कारण प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद के लिए मुकेश कुमार पाण्डेय एवं संजय कुमार गुप्ता एवं महामंत्री पद के लिए अजमत अकरम एवं नीरज गुप्ता के चुनाव की कार्यकारिणी के माध्यम से सम्पन्न करायी गयी। मतदान के पश्चात मतगणना चुनाव अधिकारी अजय कुमार सहायक कोषाधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी के निगरानी में करायी गयी। मतगणना का परिणाम सम्मिलित पूर्ण सदस्य 21 के मतदान के पश्चात अध्यक्ष पद के मुकेश कुमार पाण्डेय को 11 मत एवं संजय कुमार गुप्ता को 10 मत मिले मुकेश कुमार पाण्डेय को 1 मत से विजय घोषित किया गया। महामंत्री पद पर अजमत अकरम को 11 मत पाकर विजयी घोषित हुए व नीरज गुप्ता को 10 मत पाकर दुसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। इसके साथ कार्यकारीगण के सदस्यो का चुनाव निर्विरोध घोषित हुए। जिसमें अनुभव श्रीवास्तव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विनोद कुमार पाण्डेय उपाध्यक्ष, मोहम्मद आसिम संयुक्त मंत्री, प्रियेश कुमार सिंह कोषाध्यक्ष, कुन्दन कुमार गुप्ता संयुक्त मंत्री, शिवानन्द कुमार चतुर्वेदी मीडिया प्रभारी, सम्पत कुमार सम्प्रेक्षक, संजय कुमार गुप्ता संरक्षक मनोनित किये गये।

राज्यपाल रमेन डेका ''प्लेसमेंटनामा'' के समापन समारोह में हुए शामिल, समारोह में युवाओं को दी सफलता की सीख

युवाओं को प्रदान किया जॉब लेटर

दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका मंगलवार को दुर्ग,भिलाई के एक दिवसीय प्रवास पर रहे। इस दौरान राज्यपाल ने रूंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी, भिलाई में आयोजित भव्य कार्यक्रम 'सच हुए सपने' में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं के लिए आयोजित किए गए विशाल रोजगार मेले 'प्लेसमेंटनामा' के गौरवशाली समापन का प्रतीक था। इस दौरान राज्यपाल श्री डेका ने प्लेसमेंट के द्वारा चयनित युवाओं को जॉब लेटर प्रदान किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि 'सच हुए सपने' के माध्यम से 1,702 मेधावी युवाओं को सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हुआ है, जो राज्य के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में 'प्लेसमेंटनामा' की सफलता के आंकड़ों की सराहना करते हुए बताया कि इस पांच दिवसीय आयोजन में 10,842 युवाओं ने पंजीयन कराया और लगभग 7,000 साक्षात्कार हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज का युग केवल डिग्री का नहीं, बल्कि दक्षता, आत्मविश्वास और व्यावहारिक सोच का है। युवाओं को सफलता का मंत्र देते हुए राज्यपाल ने तीन महत्वपूर्ण बातें साझा कीं- निरंतर सीखने की जिज्ञासा बनाए रखना, ईमानदारी व स्पष्टता को अपनाना और 'मैं' से 'हम' की टीम भावना को विकसित करना। उन्होंने कहा कि जब संस्थान, उद्योग और सरकार मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे ही असाधारण परिणाम प्राप्त होते हैं।

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि इस आयोजन में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों का उत्साहजनक सहयोग रहा। आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोर इंडस्ट्री की समान भागीदारी ने यह साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ का युवा हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में एचआर प्रतिनिधियों की उम्मीदें बदल चुकी हैं। अब केवल हाँ में हा मिलाने से नौकरी नहीं मिलती, बल्कि विषय का गहन ज्ञान और व्यक्तित्व में झलकने वाला आत्मविश्वास ही आपकी असली पहचान है। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए राज्यपाल ने कहा कि रिक्रूटर्स बेहद स्मार्ट होते हैं जो चंद मिनटों में आपकी क्षमता को परख लेते हैं। इसलिए आपकी आंखों का आत्मविश्वास और भाषा की स्पष्टता ही आपका भविष्य तय करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिग्री केवल एक शुरुआत है, असली शिक्षा जीवन के अनुभवों से आती है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसके विकास के द्वार बंद हो जाते हैं।

राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि ईमानदारी और स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है; जो नहीं आता उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक मजबूत व्यक्तित्व की निशानी है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि श्प्लेसमेंटनामाश् का यह मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है, जहाँ शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर सीधे रोजगार और राष्ट्र निर्माण से जुड़ती है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आपकी सफलता ही 'नए छत्तीसगढ़' और 'नए भारत' की नींव है। स्वयं पर अटूट भरोसा रखें, क्योंकि आज का आपका सपना ही कल के भारत का गौरव बनेगा।

इस अवसर पर कलेक्टर अभिजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, विधायक रिसाली रिकेस सेन, विधायक भिलाई नगर देवेन्द्र यादव, चांसलर संतोष रूंगटा एवं संजय रूंगटा, वाइस चांसलर जवाहर सुनील सेट्ठी, रूंगटा यूनिवर्सिटी के फेकल्टी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक व युवा उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com